mediaauditornews@gmail.com Epaperdainikmediaauditor.in वर्ष-02 अंक-197 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

मनेन्द्रगढ़
18 जुलाई 2026 शनिवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

मनेन्द्रगढ़, रीवा एवं सतना से एक साथ प्रकाशित

: ब्रीफ बॉक्स :

12 साल के बच्चे को मगरमच्छ जिंदा खा गया

बहराइच में पैर जबड़े में दबाकर खींच ले गया, बच्चा तड़पता रहा...चाचा चिल्लाते रह गए

बहराइच,एजेंसी। यूपी के बहराइच से रोंगटे खड़े करने वाली घटना सामने आई है। यहां मगरमच्छ 12 साल के बच्चे को जिंदा खा गया। धान की रोपाई करने के बाद बच्चा नदी में हाथ-पैर धोने गया था, तभी मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। उसे जबड़े में दबोच लिया।

बच्चे ने खुद को छुड़ाने के लिए हाथ-पैर मारे।उसके चाचा और ग्रामीणों ने भी ईंट-पत्थर फेंककर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने उसे छोड़ा नहीं। उसने दो-तीन बार बच्चे को उछालकर पानी में पटका, फिर गहरे पानी में खींच ले गया। देखते ही देखते बच्चे के आधे शरीर को निगल लिया। 5 घंटे बाद ग्रामीणों ने बच्चे का शव बरामद किया। घटना गुरुवार शाम की है। लेकिन इसका वीडियो शुक्रवार सुबह सामने आया। थाना प्रभारी टीएन मौर्या ने घटना और वीडियो की पुष्टि की है। वन रेंजर साकिब अंसारी ने बताया- मगरमच्छ बच्चे का दाहिना पैर और कमर के नीचे का हिस्सा खा गया। मामला जिला मुख्यालय से 45 किमी दूर बौंडी थाना क्षेत्र का है।

ऐतिहासिक उड़ान: स्काईरूट का 'विक्रम-1' रचेगा इतिहास

आज लॉन्च होगा भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट

अमरावती,एजेंसी। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में अब एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। इसके तहत हैदराबाद की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप कंपनी 'स्काईरूट एयरोस्पेस' के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। इसका नाम 'मिशन आगमन' रखा गया है।इस मिशन के तहत यह ऐतिहासिक लॉन्च शनिवार सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से होगा। इस रॉकेट का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के सम्मान में 'विक्रम-1' रखा गया है।

विक्रम-1 की खासियत क्या-क्या?

बता दें कि विक्रम-1 की सबसे बड़ी खासियत इसका पूरी तरह से 'कार्बन-कंपोजिट' ढांचे से बना होना है।

वांगचुक बोले:20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहता हूं

इसी दिन कॉकरोच पार्टी का संसद मार्च; डॉक्टर बोले- वांगचुक के ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ा

नई दिल्ली,एजेंसी।दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का शुक्रवार को 20वां दिन है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी कीमत पर 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहते हैं।वांगचुक ने 20 जुलाई को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में समर्थकों से बड़ी संख्या में जुटने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बात रखेंगे।वांगचुक ने कहा कि वह बाहर से कमजोर हैं, लेकिन अंदर से मजबूत हैं। उन्होंने मजाक में कहा कि अगर 20 जुलाई का मार्च सफल नहीं हुआ, तो वह भूत बनकर वापस आएंगे।डॉक्टरों ने कहा कि वांगचुक के ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को उनकी रोजाना मेडिकल जांच कराने के निर्देश दिए थे।वांगचुक ह्रश्वश्वञ्ज पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। उनका वजन 8.9द्मद्द तक गिर गया है।

सीजेपी का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नीट पेपर लीक के विरोध में 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वांगचुक भी उनके आंदोलन में शामिल हैं। CJP चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से करने के बाद बनी थी।

मानसून सत्र 20 जुलाई से, सरकार 7 बिल लाएगी

वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदे पर सख्ती की तैयारी, परिसीमन बिल का जिक्र नहीं

नई दिल्ली,एजेंसी।20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार ने एजेंडा तय कर लिया है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, लोकसभा में 7 बिल पेश किए जाएंगे।इनमें वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदा कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक भी शामिल हैं। बिलों की अस्थायी सूची में अभी किसी भी संविधान संशोधन बिल जैसे परिसीमन या नारी संशोधन का जिक्र नहीं है।

13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में कांग्रेस समेत विपक्षी दल NEET-UG पेपर लीक, अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद, ई20 ईंधन और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं।

7 में से 2 बिल पुराने, 3 पहली बार पेश होंगे: सात में से दो विधेयक फॉरेन कंट्रीब्यूशन (FCRA) और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान पुराने हैं। विदेशी चंदे से जुड़ा विधेयक 25 मार्च 2026 को और शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। शिक्षा से जुड़े बिल को जॉइंट कमेटी के पास भेज दिया गया था। इनकम टैक्स बिल, 2026 और सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ाने वाले बिल अध्यादेशों का स्थान लेंगे।

ट्रम्प बोले:2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई

चीन ने 22 करोड़ वोटर्स का डेटा चुराया, खुफिया एजेंसियों ने जानकारी छिपाई

वॉशिंगटन डीसी,एजेंसी।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को चुनाव सुरक्षा पर राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई थी।ट्रम्प ने कहा कि उनकी सरकार चुनाव सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक यानी डिक्लासिफाई कर रही है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी इन दस्तावेजों के मुताबिक, चीन ने 2020 के चुनाव के दौरान 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों का डेटा चुराया था। ट्रम्प के अनुसार, 18 राज्यों का वोटर डेटा हैक या हासिल किया गया।ट्रम्प ने आरोप लगाया कि और दूसरी खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी थी, लेकिन इसे राष्ट्रपति, कांग्रेस और जनता से छिपाया गया।

बंगाल के मुर्शिदाबाद में ट्रेन की स्कूल वैन से टक्कर,3 की मौत

कई गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी

कोलकाता,एजेंसी।पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन ने एक पूल कार (स्कूली गाड़ी) को टक्कर मार दी। अधिकारियों के मुताबिक, टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई है, जिनमें दो स्कूली छात्र शामिल हैं।

गाड़ी रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश कर रही थी। टक्कर में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल तीन छात्रों और वैन के ड्राइवर को इलाज के लिए मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया है। अस्पताल में भर्ती कराए गए लोगों में से कुछ की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है।

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, जब एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी तब रेलवे क्रॉसिंग बंद थी। लेकिन उसके तुरंत बाद गेट को खोल दिया गया, जबकि वहां से एक पैसेंजर ट्रेन भी गुजरने वाली थी। स्कूल वैन के ड्राइवर ने गेट खुला देखकर गाड़ी को पटरियों के पार ले जाने की कोशिश की।

इसी दौरान एक साइकिल सवार भी पटरी पार करने लगा। तभी तेज रफ्तार में आ रही निमतिया-कटवा लोकल ट्रेन ने स्कूल वैन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और बच्चे अंदर ही फंस गए।

पुरी रथयात्रा, तीनों रथ गुंडिचा मंदिर पहुंचे:

अब तीनों देवता 9 दिन मौसी के घर रहेंगे, दूसरे दिन 9 लाख श्रद्धालु जुटे

पुरी,एजेंसी। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ शुक्रवार दोपहर गुंडिचा मंदिर पहुंच गए। अब तीनों देवता 9 दिन अपनी मौसी के घर रहेंगे। इसके साथ ही रथयात्रा पूरी हुई।

इसके पहले रथयात्रा शुक्रवार सुबह दूसरे दिन शुरू हुई। बह बारिश और उमस के बीच 9 लाख श्रद्धालु फिर से रथ खींचने के लिए ग्रैंड रोड पर जुटे।गुरुवार को पाहंडी अनुष्ठान में हुई देरी और अंधेरा होने के कारण तीनों रथ गुंडिचा मंदिर तक नहीं पहुंच सके थे। तीनों देवता रातभर अपने-अपने रथों पर ही विराजमान रहे।श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पाधी ने बताया कि सभी अनुष्ठान समय पर हुए, लेकिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा मुख्य द्वार पर करीब 40 मिनट तक आगे नहीं बढ़ सकी। इसी वजह से पाहंडी अनुष्ठान एक घंटे से अधिक देर से पूरा हुआ।

उन्होंने बताया कि भगवान बलभद्र का तालध्वज रथ ग्रैंड रोड पर करीब 700 मीटर चलकर मार्केट चौक पर रुका। देवी सुभद्रा का दर्पदलन रथ लगभग 400 मीटर चलकर मरीचिकोट चौक तक पहुंचा। वहीं भगवान जगन्नाथ का नंदीघोष रथ कुछ ही दूरी तय कर मुख्य मंदिर के सिंहद्वार के पास रुक गया था।

भोजशाला के पास नहीं मस्जिदों में ही जुमे की नमाज

प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला; नमाज के लिए वैकल्पिक जगह को लेकर बैठक

धार,एजेंसी।भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के 14 जुलाई के अंतरिम विस्तृत आदेश धार जिला प्रशासन को मिल गए हैं। हालांकि मुस्लिम समाज ने जुमे की नमाज घरों और मस्जिदों में ही अदा की। आदेश मिलने के बाद कलेक्ट्रेट में कलेक्टर राजीव रंजन मीना और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा की मौजूदगी में प्रशासन की अहम बैठक हुई।बैठक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई तथा भोजशाला के पास खुले वैकल्पिक स्थान पर जुमे की नमाज की व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई।इसके बाद कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ अलग बैठक आयोजित की गई। इसमें नमाज के लिए उपयुक्त स्थान तय करने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रशासन आगे की व्यवस्थाओं और फैसलों की जानकारी देगा।

आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12 मामले, 4 मौत

जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजे गए सैंपल, पड़ोसी राज्य कर्नाटक में बरती जा रही सावधानी

अमरावती,एजेंसी। आंध्र प्रदेश में 26 जून से 16 जुलाई के बीच कोरोना संक्रमण के 12 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4 मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य सरकार ने वायरस के वैरिएंट का पता लगाने के लिए 5 सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV), पुणे भेजे हैं। उधर पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी सावधानियां बढ़ा दी गई हैं।

आंध्र प्रदेश की स्वास्थ्य सचिव और कमिश्नर वीरा पांडियन के मुताबिक, जिन 4 मरीजों की मौत हुई, वे पहले से ही गंभीर बीमारियों जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज और किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। राज्य में अब तक कुल 339 कोरोना मामले सामने आए हैं, जिनमें से 12 आंध्र प्रदेश के हैं।आंकड़ों के अनुसार, कडपा में 8, गुंटूर में 2, विशाखापत्तनम और काकीनाडा में 1-1 मामला दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये मामले अलग-अलग इलाकों से हैं और कहीं भी क्लस्टर नहीं बना है।

फिलहाल 3 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और 2 अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 3 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं।विशाखापत्तनम के KGH अस्पताल की सुपरिटेंडेंट डॉ. वाणी ने बताया कि वहां एक मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। लक्षण दिखने पर डॉक्टर ने उसे टेस्ट की सलाह दी थी।

निजी लैब में पुष्टि के बाद KGH अस्पताल में भी दोबारा जांच की गई, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई।

प्रशासन की अपील- घबराएं नहीं

आंध्र प्रदेश की स्वास्थ्य सचिव वीरा पांडियन ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि राज्यभर के अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। देशभर में 1 जुलाई से अब तक 339 कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं।

पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी सावधानी बरती जा रही

कोराना के नए मामलों को देखते हुए आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी सावधानी बरती जा रही है। तुमकुरु जिले की डिप्टी कमिश्नर शुभा कल्याण ने कहा, 'आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। हमारे तुमकुरु जिले की कुछ तहसीलें, जैसे पावागड़ा, आंध्र प्रदेश की सीमा से लगी हुई हैं।

भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू

हरियाणा में जींद से सोनीपत तक 89किमी. का रूट

पीएम बोलः यह दुनिया में सबसे लंबी और ताकतवर

सोनीपत,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चली। इसके साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला भारत दुनिया का पांचवां देश बन गया है। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में ही हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं।

पीएम मोदी ने कहा- 'जींद-सोनीपत के बीच चलने वाली यह ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। इस ट्रेन को भारत के इंजीनियरों ने डिजाइन किया है और भारत की ही कंपनी ने बनाया है। '

10 कोच वाली यह ट्रेन जींद-सोनीपत रूट पर 14 स्टेशनों के बीच अधिकतम 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसका किराया 5 से 25 रुपए के बीच रखा गया है। ट्रेन 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा करेगी।

पीएम मोदी ने एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, दो मेडिकल कॉलेजों समेत 8 प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया।

स्वच्छता को बनाइए अपना संस्कार

प्रधानमंत्री ने जींद और हरियाणा के लोगों की स्वच्छता अभियान में भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले एक हफ्ते से वह सोशल मीडिया पर सफाई अभियान देख रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा कि स्वच्छता के लिए मोदी के आने का इंतजार नहीं होना चाहिए। यदि जींद के लोग संकल्प ले लें, तो स्वच्छता को अपना स्वभाव और संस्कार बनाकर हर दिन की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं।

रेलवे में बड़ा बदलाव, डीजल पर निर्भरता हुई कम

प्रधानमंत्री ने कहा कि 1925 से 2014 तक करीब 90 वर्षों में देश के रेल नेटवर्क का केवल 30 प्रतिशत बिजलीकरण हुआ था, जबकि 70 प्रतिशत हिस्सा डीजल पर निर्भर था। पिछले 12 सालों में करीब 99 प्रतिशत रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। यदि होर्मुज स्ट्रेट में युद्ध जैसी स्थिति 2014 से पहले बनती तो डीजल आपूर्ति प्रभावित होने से रेलवे भी संकट में आ सकता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।

खेलों में हरियाणा के युवाओं पर जताया भरोसा

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा और 2036 ओलिंपिक की मेजबानी के लिए भी प्रयास कर रहा है। सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा देगी। भारत न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और खिलाड़ियों के ट्रेनिंग के क्षेत्र में मिलकर काम करेगा, जिसका लाभ हरियाणा के युवाओं को मिलेगा।

युद्ध का असर भारत पर पड़ता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि होर्मुज स्ट्रेट में युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो इसका असर भारत पर भी पड़ता है, क्योंकि इसी समुद्री मार्ग से देश में पेट्रोल, डीजल और खाद समेत कई जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति होती है।उन्होंने कहा कि यदि 2014 से पहले ऐसी स्थिति पैदा होती, तो देश का रेलवे नेटवर्क गंभीर संकट में आ जाता, क्योंकि उस समय रेलवे का बड़ा हिस्सा डीजल इंजनों पर निर्भर था। ऐसे में यदि डीजल की आपूर्ति बाधित हो जाती, तो ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हो सकता था।प्रधानमंत्री ने कहा कि अब स्थिति बदल चुकी है। उन्होंने कहा, 'यह 2014 से पहले वाला भारत नहीं है। यह नया भारत है। यह मोदी है, जो बहुत पहले सोचता भी है और समस्याओं के समाधान को समय रहते जमीन पर भी उतारता है। 'प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में रेलवे के बिजलीकरण की शुरुआत वर्ष 1925 में हुई थी। यानी 1925 से लेकर 2014 तक करीब 90 वर्षों में देश के रेल नेटवर्क का केवल 30 प्रतिशत ही बिजलीकृत हो पाया था, जबकि 70 प्रतिशत हिस्सा अब भी डीजल इंजनों पर निर्भर था।

सीएम शुभेंदु ने इस्कॉन की भव्य रथयात्रा का किया शुभारंभ; खींची पवित्र रथ की रस्सी

कोलकाता, एजेंसी। कोलकाता के अल्बर्ट रोड स्थित इस्कॉन मंदिर में गुरुवार को ऐतिहासिक 55वें वार्षिक रथयात्रा महोत्सव की शुरुआत बेहद भव्य तरीके से हुई। बंगाल में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस पावन उत्सव का औपचारिक उद्घाटन करने के लिए विशेष रूप से उपस्थित हुए। बारिश और भक्तिमय माहौल के बीच पीले कुर्ते और सफेद धोती में पहुंचे मुख्यमंत्री ने न केवल राधामाधव के विग्रह की महाआरती की, बल्कि पारंपरिक 'छेडा पहनरा' (सोने की झाड़ू से रथ के मार्ग की सफाई) की रस्म अदा कर भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचकर कोलकाता में इस्कान की वार्षिक रथयात्रा का शुभारंभ किया। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद यह पहला अवसर है, जब शुभेंदु ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने साष्टांग प्रणाम कर राज्य की खुशहाली की कामना की और भक्तिभाव में डूबकर गौड़ीय संगीत की दो पंक्तियां भी गाईं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इस्कान के संस्थापक श्रील प्रभुपाद के कक्ष को 'हेरिटेज' घोषित करने के लिए केंद्र सरकार से आवेदन करने की भी घोषणा की।

धार्मिक मंच से प्रशासनिक सुधार और शुचिता का संकल्प: इस पावन और धार्मिक मंच से मुख्यमंत्री ने राज्य में 'मिड-डे मील योजना' में किए गए बदलाव के बाद जारी विवाद पर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया। स्कूलों में बच्चों को भोजन वितरण की जिम्मेदारी इस्कान को सौंपने के फैसले का पुरजोर समर्थन करते हुए उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि बीते वर्षों में बंगाल में मिड-डे मील को लेकर जो कुछ भी हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण था। मासूम बच्चों के भोजन में हेराफेरी करना महापाप है। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं होगी।

मिड डे मील से अंडा हटाने पर छिड़े विवाद का दिया सीधा जवाब: सरकारी स्कूलों में एक अगस्त से लागू होने जा रही मिड डे मील की नई व्यवस्था और इस्कान के पूर्णतः शाकाहारी नियमों के कारण भोजन सूची से अंडा हटाए जाने पर विशेषज्ञों द्वारा उठाए जा रहे सवालों का मुख्यमंत्री ने बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मिड-डे मील का लक्ष्य केवल पेट भरना नहीं, बल्कि पोषण सुनिश्चित करना है। सरकारी स्कूलों में आने वाले बच्चे ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं, इसलिए उन तक स्वच्छ, पवित्र और पुष्टिकर भोजन पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है।

बंगाल के नव-निर्माण में आध्यात्मिक संस्थाओं का सहयोग

शुभेंदु ने इस दौरान एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आगामी दिनों में मायापुर को 'नोटीफाइड एरिया अथारिटी' बनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाल के नव-निर्माण और सामाजिक कल्याण की राह में सरकार इस्कान, रामकृष्ण मठ और मिशन, तथा भारत सेवाश्रम संघ जैसी प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर चलेगी।

संस्कृति को बढ़ावा 60 रथयात्रा समितियों को तीन करोड़ का अनुदान

संस्कृति को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने इस वर्ष पहली बार बंगाल की कुल 60 पारंपरिक रथयात्रा समितियों को 5-5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता (कुल तीन करोड़ रुपये) दी गई है। कोलकाता के बाद मुख्यमंत्री अपने गृह जिले पूर्व मेदिनीपुर के तमलूक और मेचेदा में आयोजित रथयात्रा कार्यक्रमों में भी शामिल हुए।

देश की सबसे बड़ी जल सुरंग तैयार, 12 किमी की टनल से बुझेगी छह जिलों के खेतों की प्यास

कटनी, एजेंसी। देश की सबसे बड़ी जल सुरंग मध्य प्रदेश में तैयार हो गई है। महाकोशल अंचल के जबलपुर जिले से विंध्य अंचल तक नर्मदा के जल को खेतों में पहुंचाने के लिए कटनी जिले के स्लीमनाबाद में इसे तैयार किया गया है। नर्मदा की अमृतधारा को बिना पंप की सहायता से प्राकृतिक बहाव के साथ सोन बेसिन से जोड़ने के लिए यह सेतु का कार्य करेगी। 12 किमी लंबी और 10.14 मीटर व्यास वाली इस सुरंग से महाकोशल-विंध्य के छह जिलों की दो लाख 45 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। बरगी व्यपवर्तन परियोजना के दाएं तट पर मुख्य नहर की इस टनल का कार्य करीब 15 साल चला। स्थानीय लोग बताते हैं कि परियोजना शुरू होने के समय पैदा हुए बच्चे बड़े हो गए। सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहली शिफ्ट में काम करने वाले मजदूर बुजुर्ग हो गए। कुछ सहकर्मी इस सफलता को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। मशीनें बदल गईं, ठेकेदार बदल गए, अधिकारी बदल गए पर पहाड़ के नीचे काम चलता रहा। अमेरिका और जर्मनी की मशीनों से पहाड़ का सीना चीरने में कई बाधाएं भी आईं। कार्यपालन यंत्री सहज श्रीवास्तव के मुताबिक, सलैया फाटक से लेकर खिरहनी गांव तक पहाड़ों के नीचे बनी सुरंग देश की सबसे बड़ी जल सुरंग है। टनल का काम पूरा होने के साथ ही साफ्ट तक मशीन पहुंच गई है और अब उसको बाहर निकालने का कार्य शुरू किया जा रहा है।

अनेक बाधाओं के बाद मिली सफलता: परियोजना को 799 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2008 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्लीमनाबाद में इस अंडरग्राउंड टनल का कार्य 2011 में प्रारंभ होकर 40 माह में पूरा होना था। लगातार बाधाओं के कारण काम लेट होता गया। मशीनों के कटर टूटने, पानी का बहाव अधिक होने, मिट्टी के धंसने के साथ सलैया फाटक के पास रेलवे लाइन के नीचे से टनल निकालने में स्वीकृति मिलने में छह-छह माह का समय लगा और इस दौरान काम बंद रखना पड़ा। 2022 में मशीन का कटर सुधारने के लिए उसे बाहर निकालने के दौरान बनाए गए सॉफ्ट के धंसने से नौ मजदूर भी उसमें दब गए थे और दो की मौत हो गई थी। देरी के साथ ही योजना की लागत बढ़कर 1600 करोड़ रुपये पहुंच गई। कटनी का 21 हजार 823 हेक्टेयर, मैहर का 54 हजार 227 हेक्टेयर, सतना का एक लाख चार हजार 970 हेक्टेयर, पन्ना का 448 हेक्टेयर और रीवा का तीन हजार 84 हेक्टेयर क्षेत्र सीधे लाभान्वित होगा।जबलपुर जिले की भी लगभग 60 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। छह जिलों के 1450 गांवों को इससे लाभ मिलेगा। अक्टूबर माह से नर्मदा का जल विंध्य तक पहुंचाने की योजना है।

सड़क के ऊपर दौड़ेगी मेट्रो केशव पुरम से रोहिणी का सफर होगा आसान, दिल्ली को मिलने जा रहा एक और डबल डेकर फ्लाईओवर

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी में मेट्रो नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केशव पुरम से रोहिणी सेक्टर 34 के बीच 16.5 किलोमीटर लंबा कारिडोर बनाने का प्रस्ताव है। इसे डबल डेकर कारिडोर के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने व्यवहार्यता अध्ययन कराने का निर्णय लिया है। मेट्रो के पांच (बी) चरण में केशव पुरम से रोहिणी सेक्टर तक मेट्रो कारिडोर का निर्माण किया जाना है। इसे मेट्रो व सड़क मार्ग के लिए एकीकृत डबल डेकर के रूप में विकसित करने के लिए छह में व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया जाएगा। इस पर 2.8 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके लिए चयनित सलाहकार विस्तृत यातायात और परिवहन विकल्प, बनावट, इंजीनियरिंग चुनौती, परियोजना पर अनुमानित लागत सहित अन्य आवश्यक बिंदुओं पर अध्ययन करेगा। उसकी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में भूमि की कमी को ध्यान में रखकर डबल डेकर कारिडोर विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली में पिंक लाइन पर मजलिस पार्क-मौजपुर कॉरिडोर पर भजनपुरा-यमुना विहार खंड पर 1.4 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर तैयार किया गया है। वहीं, एमबी रोड पर साकेत जी ब्लाक से पुल प्रह्लादपुर तक डबल डेकर एलिवेटेड कारिडोर तैयार किया जा रहा है।

नक्शा तो किसी यूनिवर्सिटी का पास नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी ने पूछा- जौहर की तरह सभी पर चलेगा बुलडोजर

रामपुर , एजेंसी। यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां की जौहर विश्वविद्यालय का नक्शा पास नहीं होने के कारण उसे ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। इसे लेकर प्रशासन के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला हुआ है। अब कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इसे लेकर पूछा कि नक्शा तो किसी यूनिवर्सिटी का पास नहीं है। क्या जौहर यूनिवर्सिटी की तरह सभी पर बुलडोजर चलाया जाएगा इमरान ने कहा कि जब जौहर युनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था, बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बड़ा कर लिया। अब रामपुर के डीएम कह रहे हैं कि जौहर युनिवर्सिटी का नक्शा नहीं पास है तो गिराने का आदेश पारित कर दिया गया है। इमरान ने कहा कि नक्शा तो इस देश के ज्यादातर छ्रू ऑफिस का भी नहीं पास होगा तो क्या सब को ज़मींदोज़ कर दोगे? ऐसे बेतुके और तानाशाही वाले आदेश पारित करते हुए अधिकारियों को सोचना चाहिये कि ये भी किसी ऐसी ही यूनिवर्सिटी से पढ़कर आये होंगे, जहां का नक्शा नहीं पास होगा। इमरान ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कहा कि शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को बचाने के लिये सभ्य समाज को आगे आना होगा वरना ये ज़ालिम सरकारें कुछ भी महफ़ूज़ नहीं रहने देंगी।

क्या है जौहर विश्वविद्यालय को लेकर आदेश: रामपुर विकास प्राधिकरण ने आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए परिसर में बने 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। प्राधिकरण ने इन भवनों को बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्मित मानते हुए पूरी तरह अवैध घोषित किया है। गुरुवार को जौहर विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस भी तामिल करा दी गई। इसमें 15 दिन में खुद ध्वस्तीकरण करने की चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि खुद ध्वस्त नहीं करने पर रामपुर विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण करेगा और खर्च की वसूली भी की जाएगी।

जौहर विवि के कब्जे से मुक्त हुआ 3.5 किमी का फोरलेन: इससे पहले करीब 13.50 करोड़ की लागत से बनी फोरलेन सड़क पर प्रशासन ने कब्जा ले लिया। पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अधिकारियों ने जौहर विवि पहुंचकर आम रास्ता होने के बोर्ड लगवाए। 2003-04 में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान आजम खां ने जौहर विश्वविद्यालय के प्रस्तावित मानचित्र में मौजूद मुख्य द्वार से होते हुए लोक निर्माण विभाग से लगभग साढ़े तीन किमी लंबी सड़क का निर्माण करा लिया था।

प्रदेश में दोबारा सपा सरकार बनने पर आजम खां ने विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा करा लिया।

यूपी समेत 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका

लखनऊ, पटना, एजेंसी। देशभर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी आगामी दिनों में छिटपुट बारिश के साथ आकाश में बादल छाए रहने की संभावना है। विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, गोवा, झारखंड, सिक्किम, असम, हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इससे सटे उत्तर ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट पर बने सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अगले सात दिनों के दौरान वर्षा गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज ओडिशा में कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। इस सिस्टम के असर से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी बारिश बढ़ेगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी आगामी दिनों में छिटपुट बारिश के साथ आकाश में बादल छाए रहने की संभावना है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश से नदियों में जल स्तर बढ़ सकता है और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर घाटी में लगातार बारिश से मौसम ठंडा रहेगा। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में उमस भरी गर्मी के बीच बीच-बीच में हल्की-मध्यम बारिश राहत दे सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले एक सप्ताह तक मूसलाधार बारिश की संभावना है, जिससे जलभराव और निचले इलाकों में पानी जमा होने की आशंका बनी रहेगी। किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने सभी प्रभावित राज्यों के प्रशासन को अलर्ट रहने और संभावित नुकसान से बचाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। आम जनता को भारी बारिश वाले दिनों में अनावश्यक यात्रा से बचने और पहाड़ी क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

15 दिन 48 हमले: बलूचिस्तान में 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा; पाक सेना ने साधी चुप्पी

क्वेटा, एजेंसी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच बलूचिस्तान के विभिन्न हिस्सों में 48 हमले किए। संगठन के मुताबिक इन समन्वित अभियानों में 40 से अधिक पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हुए। बीएलए का कहना है कि उसके निशाने पर सैन्य काफिले, सुरक्षा चौकियां, पुल और सेना की रसद आपूर्ति से जुड़े मार्ग रहे। बीएलए के प्रवक्ता जीयंद बलूच की ओर से जारी बयान में कहा गया कि संगठन के लड़ाकों ने 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच मस्तुंग, नुश्की, केच, सूराब, खुजदार, जियारत, खारान और कलात जिलों में हथियारबंद हमले और आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) विस्फोट किए।

1 जुलाई को क्या हुआ था: बीएलए के अनुसार, 1 जुलाई को मस्तुंग के दश्त इलाके में सेना की रसद सामग्री ले जा रहे एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें दो पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। संगठन ने यह भी कहा कि उसने नुश्की और पंजगुर में मालवाहक वाहनों पर हमले किए, जिन्हें उसने अपने कथित 'आर्थिक नाकेबंदी अभियान' का हिस्सा बताया।

3 जुलाई को किन ठिकानों को निशाना बनाया गया: संगठन का दावा है कि 3 जुलाई को नुश्की और मस्तुंग में आईईडी हमलों में कम से कम दो सुरक्षा कर्मी मारे गए और सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचा, जिसमें एक पुल भी शामिल था। क्वेटा ने यह भी दावा किया कि उसने हरनाई, जियारत और दलबंदीन के राजमार्गों पर अस्थायी नाकेबंदी की, पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में लिया तथा कई पुलों और व्यावसायिक वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया।

आगे के दिनों में किन हमलों का दावा किया गया: बीएलए ने दावा किया कि इसके बाद केच, नुश्की और खुजदार में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। संगठन के मुताबिक सैन्य शिविरों पर ग्रेनेड हमले किए गए, गश्ती दलों पर हमला किया गया और अहमद वाल में एक पुलिस थाने पर कुछ समय के लिए कब्जा करने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया।

हसीना का प्रत्यर्पण: बांग्लादेश को भारत के जवाब का इंतजार, क्या लौटते ही होगी गिरफ्तारी मंत्री ने कर दिया साफ

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश ने भारत से अपनी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर जल्द सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की उम्मीद जताई है। बांग्लादेश सरकार ने कहा कि वह भारत में मौजूद उन सभी आरोपियों की वापसी चाहता है, जो देश में सजा पा चुके हैं या गंभीर अदालती मुकदमों का सामना कर रहे हैं। 78 वर्षीय शेख हसीना पिछले साल अगस्त में हिंसक छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद अपनी सरकार गिरने पर अचानक भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में ही रह रही हैं।

नवंबर में एक विशेष अदालत ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उनकी अनुपस्थिति में ही मौत की सजा सुनाई थी। शेख हसीना ने इन सभी अदालती

फैसलों और आपराधिक आरोपों को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है। हाल ही में शेख हसीना ने खुद ही दिसंबर तक स्वेच्छा से वतन वापसी की बात कही थी।

क्या शेख हसीना की वापसी पर होगी तुरंत गिरफ्तारी: बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने इस संवेदनशील मामले पर सरकार का रुख पूरी तरह साफ कर दिया है।

ट्रंप का चलेगा चाबुक: अमेरिका में अवैध ट्रक चालकों को देश से निकालने की तैयारी, जानें भारत पर क्या पड़ेगा असर

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह अवैध अप्रवासी ट्रक चालकों पर व्यापक कार्रवाई की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी सड़कों पर अवैध रूप से काम करने वालों को हटा देगा। इसके साथ ही एक नई लाइसेंसिंग पहल के तहत उनकी जगह सैन्य दिग्गजों को नियुक्त करेगा। बुधवार को पेंसिल्वेनिया रक्षा और नवाचार शिखर सम्मेलन में बोलते हुए ट्रंप ने प्रस्तावित कार्रवाई को पेंसिल्वेनिया राज्य के पुलिस अधिकारी माइकल पहिरा की हाल ही में हुई मौत से जोड़ा, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उनकी हत्या एक अवैध अप्रवासी द्वारा वाणिज्यिक चालक लाइसेंस पर सेमी-ट्रक चलाने के कारण हुई थी।

राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या आरोप लगाए : ट्रंप ने कहा, 'आज मैं एक और महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूं। मेरा प्रशासन जल्द ही उन अवैध ट्रक चालकों के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई करेगा जो बड़ी संख्या में लोगों की जान ले रहे हैं।' उन्होंने आरोप लगाया कि बिना लाइसेंस वाले ड्राइवर साइन बोर्ड नहीं पढ़ सकते। इसके साथ ही कहा कि उनमें से कई नशे या शराब के नशे में होते हैं, और उन्हें ये वाहन नहीं चलाने चाहिए।'

'हम उन्हें नहीं चाहते: ट्रंप ने कहा, 'वे अवैध रूप से आए हैं और हम उन्हें नहीं चाहते। लेकिन वे अमेरिकी सड़कों पर हर जगह गाड़ी चला रहे हैं, और हम उनकी जगह गर्वित अमेरिकी दिग्गजों को तैनात

करेंगे।' गौरतलब है कि अमेरिकी ट्रक उद्योग में ड्राइवरों और मालिकों दोनों के रूप में सिखों का दबदबा है। इनमें से अधिकांश अमेरिकी नागरिक, स्थायी निवासी या अधिकृत कर्मचारी के रूप में कानूनी रूप से कार्यरत हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि बड़ी संख्या में सिख ड्राइवर अवैध रूप से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन यह सच नहीं भी हो सकता है।

अप्रवासियों की ड्राइविंग लाइसेंस कैसे जारी होती है: वाहन चलाने के लिए वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो राज्य सरकारों की ओर से जारी किया जाता है। कुछ मामलों में, अदालत में पेश होकर राजनीतिक शरण मांगने वाले अवैध अप्रवासियों को अस्थायी आधिकारिक कार्य परमिट जारी किए जाते हैं। इसके बाद ही उन्हें वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है, जो कठोर ड्राइविंग परीक्षा के बाद ही मिलता है।

ट्रंप प्रशासन परिवहन नौकरियों के लिए किसको मान्यता देगा: ट्रंप ने कहा कि प्रशासन वाणिज्यिक ट्रक परिवहन नौकरियों के लिए सैन्य अनुभव को मान्यता देगा। उन्होंने कहा, 'हम अपने पूर्व सैनिकों को लेंगे। उन्हें ट्रक चलाना सिखाएंगे। कई मामलों में वे जानते भी हैं। हम यह कहेंगे कि कोई भी अमेरिकी जिसने हमारी सेना के लिए भारी ट्रक चलाया है, वह स्वतः ही वाणिज्यिक चालक लाइसेंस के लिए पात्र होगा।' राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को सार्वजनिक सुरक्षा उपाय और पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए रोजगार पहल दोनों के रूप में प्रस्तुत किया।

भारतीयों पर असर पड़ेगा: बता दें कि इस कदम से अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासियों पर असर पड़ने की संभावना है। द इंडियन एक्सप्रेस की नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी ट्रकर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में लगभग 130,000 से 150,000 ट्रक चालक सीधे पंजाब और हरियाणा से आते हैं।

इस साल ट्रंप ने कौन सी कानून लागू की : इस साल फरवरी में, ट्रंप ने दलीला कानून की घोषणा की, जिसके तहत अवैध अप्रवासियों को व्यावसायिक वाहन चालक लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी अप्रवासी को ट्रक और अन्य मालवाहक वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यह कानून बेकर्सफील्ड की पांच वर्षीय दलीला के मामले पर आधारित था, जो भारत से आए एक अवैध अप्रवासी प्रताप सिंह द्वारा किए गए कई कारों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घायल हो गई थी। उसके पिता के अनुसार, इस दुर्घटना के कारण बच्ची बोल नहीं पाती है और उसे चलना फिर से सीखना पड़ रहा है। गृह सुरक्षा विभाग के अनुसार, सिंह ने 20 जून, 2024 को असुरक्षित गति से गाड़ी चलाने और यातायात और निर्माण क्षेत्र में न रुकने के कारण कई कारों की टक्कर का कारण बना।

पिछले महीने कितने भारतीय ट्रक चालक की गिरफ्तारी हुई: पिछले महीने, देश में अवैध रूप से रह रहे कम से कम 30 भारतीयों को अमेरिकी सीमा गश्ती दल के एजेंटों ने गिरफ्तार किया था। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग ने बताया कि ये भारतीय उन 52 लोगों में शामिल थे जिन्हें एरिजोना के युमा सेक्टर के एजेंटों ने 11 से 15 मई के बीच गिरफ्तार किया था। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा ने बताया 'इनमें से 30 व्यक्ति भारत से थे। बाकी छह मेक्सिको, अल सल्वाडोर और रूस से थे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों पर संघीय कानून के अनुसार कार्रवाई की गई और उन्हें निर्वासित किया जाएगा। ये गिरफ्तारियां 'ऑपरेशन चेकमेट' के तहत की गई, जो अमेरिकी सीमा शुल्क के अनुसार देश में अवैध रूप से रह रहे वाणिज्यिक मोटर वाहन चालकों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने से संबंधित है।

भुईमाड़, खाम्ह, मौरा और व्यवहारखाड़ में लगेंगे अंत्योदय स्वास्थ्य शिविर

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सीधी जिले में 18 जुलाई 2026 (शनिवार) को चार स्थानों पर अंत्योदय स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे इन शिविरों में नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, आयुष्मान कार्ड निर्माण सहित पशुपालन से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बार शिविरों में पशुपालन विभाग भी सक्रिय रूप से शामिल होगा पशुपालक अपने पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और पशुपालन संबंधी तकनीकी सलाह विभागीय विशेषज्ञों से प्राप्त कर सकेंगे इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी।

चार स्थानों पर आयोजित होंगे शिविर: मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने बताया कि जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाएंगे धौहनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भुईमाड़, सीधी विधानसभा क्षेत्र के खाम्ह, चुरहट विधानसभा क्षेत्र के मौरा तथा सिहावल विधानसभा क्षेत्र के व्यवहारखाड़ में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक शिविर लगाए जाएंगे।

इन शिविरों में ग्रामीण नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उन्हें अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

कई विभागों की संयुक्त भागीदारी: अंत्योदय स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, आयुष विभाग और पशुपालन विभाग के संयुक्त सहयोग से किया जाएगा शिविरों के सुचारू संचालन के लिए संबंधित सीडीपीओ और बीएमओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और आवश्यकतानुसार उपचार एवं परामर्श दिया जाएगा वहीं आयुष विभाग द्वारा भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

अवैध खनन पर सख्ती की तैयारी, जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक 20 जुलाई को

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की महत्वपूर्ण बैठक 20 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी बैठक दोपहर 12 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में होगी, जिसमें जिले में अवैध खनन रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों और आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन और खनिजों के अवैध भंडारण के खिलाफ की जा रही संयुक्त कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों से अब तक की गई कार्रवाई, चिन्हित क्षेत्रों और भविष्य की कार्ययोजना की जानकारी ली जाएगी बैठक में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी विशेष रूप से समीक्षा की जाएगी अभ्यारण्य क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण यहां अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल है। अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था, जांच अभियान और अवैध गतिविधियों पर की गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी इसके साथ ही भविष्य में निगरानी को और प्रभावी बनाने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा ।

सीमावर्ती क्षेत्रों की खदानों की होगी निगरानी: बैठक में जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित स्वीकृत रेत खदानों की सतत निगरानी और जांच व्यवस्था को लेकर भी चर्चा होगी प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि स्वीकृत खदानों में नियमों का पालन हो और उनकी आड़ में किसी प्रकार का अवैध उत्खनन या परिवहन न किया जा सके।

इसके लिए खनिज विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा।

अवैध खनन रोकने के लिए बनेगी प्रभावी रणनीति: जिला प्रशासन का उद्देश्य खनिज संपदा के अवैध दोहन को रोकना और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ शासन के राजस्व हितों की रक्षा करना है बैठक में अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नई रणनीति तैयार की जाएगी प्रशासन द्वारा समय-समय पर जांच अभियान चलाकर अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है टास्क फोर्स की बैठक में इन अभियानों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति रहेगी और जिले में खनिजों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए संयुक्त प्रयासों को और मजबूत करने पर निर्णय लिया जाएगा।

'युवा संगम' 29 जुलाई को एक ही मंच पर मिलेंगे रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में 'युवा संगम' (रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला) का आयोजन 29 जुलाई 2026 को किया जाएगा यह एक दिवसीय मेला प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय स्वशासी संजय गांधी स्मृति स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय, सीधी परिसर में आयोजित होगा कार्यक्रम का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के निर्धारित कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को युवा संगम का आयोजन किया जाता है हालांकि जुलाई माह में कलेक्टर के निर्देशानुसार आयोजन की तिथि में बदलाव करते हुए इसे 29 जुलाई 2026 को निर्धारित किया गया है।

युवाओं को मिलेगा रोजगार से जुड़ने का अवसर: युवा संगम का मुख्य उद्देश्य जिले के बेरोजगार युवाओं को एक ही मंच पर रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराना है। इस मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियां युवाओं का चयन करेंगी वहीं स्वरोजगार योजनाओं से संबंधित विभाग युवाओं को व्यवसाय शुरू करने और आर्थिक सहायता प्राप्त करने की जानकारी देंगे यह आयोजन जिला रोजगार कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, सीधी के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है।

कई प्रतिष्ठित कंपनियां लेंगी भाग: युवा संगम में देश, प्रदेश और स्थानीय स्तर की कई प्रतिष्ठित निजी कंपनियां शामिल होंगी। इनमें एमआरएफ टायर (गोवा), फ्लिपकार्ट (सीधी), सीआईएमसीसी (इंदौर), टीसीआई (सिंगरौली), प्रगतिशील बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड (रीवा), टाटा जेबीएम (गुजरात), एसआईएस सिक्योरिटी (सिंगरौली), युनोमिडा ईवी सिस्टम (हरियाणा), विजन इंडिया (गोवा), अवसर प्राइवेट लिमिटेड (हरियाणा), टीएसपीएल (पुणे) और करियर पैकिट बॉटल (सीधी) जैसी कंपनियां शामिल होंगी। इन कंपनियों द्वारा विभिन्न पदों के लिए युवाओं से संपर्क किया जाएगा और योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

राष्ट्रीय मंच पर सीधी के जल संरक्षण मॉडल की गूंज, वॉटर सीरीज़ वेबिनार में नासिक के साथ साझा किए नवाचार, महिलाओं की आजीविका और जनभागीदारी बनी मिसाल

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्यप्रदेश के सीधी जिले में जल संरक्षण को लेकर किए जा रहे नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है "कैच द रेन" अभियान के अंतर्गत आयोजित वॉटर सीरीज़ वेबिनार के 55वें संस्करण में सीधी और महाराष्ट्र के नासिक जिले ने अपने सफल जल संरक्षण मॉडल और नवाचारों को देशभर के विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया वेबिनार में सीधी जिले की ओर से कलेक्टर विकास मिश्रा ने जल संवर्धन के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी दी उन्होंने बताया कि जिले में जल संरक्षण को केवल प्राकृतिक संसाधनों को बचाने तक सीमित नहीं रखा गया बल्कि इसे महिलाओं की आजीविका, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी और ग्रामीण समुदाय के सहयोग से एक व्यापक जनआंदोलन का रूप दिया गया है कलेक्टर ने कहा कि सामुदायिक सहभागिता पर आधारित इस मॉडल से न केवल जल स्तर में सुधार हुआ है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। जल संरक्षण कार्यों के कारण किसानों की आय में वृद्धि हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी विकसित हुए हैं।

12 हजार से अधिक जल संरक्षण कार्यों से बढ़ी जल भंडारण क्षमता: वेबिनार में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, सीधी जिले में अब तक 12,983 जल संरक्षण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं इन कार्यों के परिणामस्वरूप जिले की जल भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है पहले जहां जल भंडारण क्षमता 1 करोड़ 35 लाख 73 हजार 874 घनमीटर थी, वहीं अब यह बढ़कर 1 करोड़ 80 लाख 56 हजार 486 घनमीटर हो गई है यानी जिले में 44 लाख 82 हजार 612 घनमीटर अतिरिक्त जल संग्रहण क्षमता विकसित की गई है इस अतिरिक्त जल उपलब्धता से लगभग 896 हेक्टेयर (करीब 2,215 एकड़) अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की संभावना है साथ ही उपलब्ध अतिरिक्त जल से लगभग एक लाख लोगों की दैनिक पेयजल आवश्यकता पूरी की जा सकती है।

नदी पुनर्जीवन अभियान से बदली तस्वीर: सीधी जिले में नदी पुनर्जीवन अभियान के तहत सभी पांचों जनपद पंचायतों में एक-एक नदी का चयन कर जल संरक्षण के विभिन्न कार्य कराए गए हैं इनमें चेकडैम, स्टॉपडैम, बोल्डर चेकडैम और गैबियन संरचनाओं का निर्माण शामिल है इन प्रयासों का असर अब दिखाई देने लगा है गर्मी के मौसम में भी कई नदियों में जल उपलब्ध रहने लगा है इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट कम हुआ है और कृषि गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है सिहावल विकासखंड के व्यवहार खांड, कुंनझुनकला, बहरी, अमराही और पोड़ी क्षेत्रों में लिफ्ट सिंचाई प्रणालियां स्थापित की गई हैं। इन प्रणालियों के माध्यम से नदी का पानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बसे आदिवासी किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक लिफ्ट सिंचाई प्रणाली से 10 से 15 किसानों को सिंचाई सुविधा मिल रही है पहले जो किसान केवल खरीफ फसल पर निर्भर रहते थे, वे अब रबी फसलों के साथ सब्जी उत्पादन भी करने लगे हैं इससे उनकी वार्षिक आय में लगभग 40 से 50 हजार रुपये तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सीधी जिले में जल संरक्षण कार्यों को आजीविका से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है इसके तहत 211 तालाबों में मत्स्य पालन और 178 तालाबों में सिंघाड़ा उत्पादन कराया जा रहा है। इन गतिविधियों से स्थानीय समुदाय को आर्थिक लाभ मिल रहा है इस वर्ष इन योजनाओं से शासन को लगभग 34 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई है जबकि मछुआ समूहों, स्व-सहायता समूहों और व्यक्तिगत मत्स्य पालकों को मिलाकर लगभग 80 लाख रुपये का प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिला है इस मॉडल ने यह साबित किया है कि जल संरक्षण केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं बल्कि ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने का प्रभावी साधन भी बन सकता है। वेबिनार में सीधी जिले के हरित आजीविका मॉडल की भी जानकारी दी गई जिले में 18,600 फलदार पौधे तैयार किए गए हैं इन पौधों के माध्यम से भविष्य में लगभग 3.59 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होने का अनुमान लगाया गया है।

कृषि धन-धान्य योजना की समीक्षा कलेक्टर ने दिए पोर्टल अपडेट और कम वर्षा की स्थिति में वैकल्पिक कार्ययोजना तैयार रखने के निर्देश

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में कृषि धन-धान्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के विभिन्न इंडिकेटर्स, विभागवार प्रगति और आगामी कार्ययोजना को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्यों को गति दें और योजनाओं की प्रगति की जानकारी नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट करें ताकि योजनाओं की प्रभावी निगरानी और समीक्षा की जा सके बैठक में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता तथा मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सहित अन्य संबंधित विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि कृषि धन-धान्य योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि उत्पादन को मजबूत करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है इसके लिए सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है कलेक्टर ने मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए सभी विभागों को संभावित कम वर्षा की स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि यदि वर्षा सामान्य से कम होती है तो किसानों और ग्रामीण परिवारों की आजीविका प्रभावित न हो इसके लिए प्रत्येक विभाग अपनी वैकल्पिक कार्ययोजना (कंटीजेंसी प्लान) तैयार रखे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कृषि गतिविधियों, पशुपालन, उद्यानिकी और अन्य आजीविका आधारित योजनाओं में समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाएं जिससे किसानों को किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में सहायता मिल सके। बैठक में कलेक्टर ने कृषि विभाग को किसानों के लिए वैकल्पिक फसलों, उन्नत कृषि तकनीकों और आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि मौसम आधारित कृषि सलाह किसानों तक समय पर पहुंचाई जाए ताकि वे बेहतर निर्णय ले सकें। उद्यानिकी विभाग को बागवानी और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कहा गया वहीं पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को किसानों की आय बढ़ाने वाले पूरक व्यवसायों को विस्तार देने के निर्देश दिए गए सहकारिता विभाग को किसानों को खाद, बीज और अन्य आवश्यक संसाधनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका आधारित गतिविधियों को और मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि कृषि धन-धान्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों को एकजुट होकर काम करना होगा।

अडानी प्लांट से 3.50 लाख की केबल चोरी का खुलासा

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले के माड़ा थाना क्षेत्र की बंधौरा पुलिस ने अडानी परियोजना के प्लांट से हुई लाखों रुपये की केबल चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 3.50 लाख रुपये कीमत की चोरी गई केबल और अन्य सामान बरामद किया है पुलिस के अनुसार 17 जून 2026 को फिराज इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के परिसर से चोरी की शिकायत मिली थी यह कंपनी अडानी परियोजना के तहत विद्युत कार्य कर रही है चोरों ने प्लांट परिसर से करीब 100 मीटर कॉपर केबल, 90 मीटर एल्यूमीनियम केबल, सीलिंग वायर और सेफ्टी बेल्ट चोरी कर लिए थे। शिकायत दर्ज होने के बाद बंधौरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकी क्षेत्र के कर्सुआलाल निवासी बबलू प्रसाद जायसवाल (32) को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की घटना को स्वीकार कर लिया उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किया गया पूरा सामान बरामद कर लिया बरामद सामग्री की कुल कीमत लगभग 3.50 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत कार्रवाई की है। बंधौरा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक संदीप नामदेव ने बताया कि तकनीकी जांच और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाली चोरी की घटनाओं पर पुलिस लगातार निगरानी रख रही है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। चेक बाउंस से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए सीधी जिला न्यायालय परिसर में 18 जुलाई 2026 (शनिवार) को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (ह्रस्र) और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आयोजित इस विशेष लोक अदालत में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। यह आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में किया जा रहा है लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करना और पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाना है। विशेष लोक अदालत के लिए न्यायालय स्तर पर खंडपीठों का गठन किया गया है अपीलीय न्यायालय के लिए रविंद्र कुमार शर्मा, तृतीय जिला न्यायाधीश की खंडपीठ बनाई गई है जबकि विचारण न्यायालय के मामलों के लिए सोनू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की खंडपीठ गठित की गई है इन खंडपीठों के माध्यम से चेक बाउंस से संबंधित मामलों में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा होने से न्यायालयों पर लंबित मामलों का भार भी कम होगा और पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार शिवहरे ने धारा 138 एनआई एक्ट से जुड़े सभी पक्षकारों से विशेष लोक अदालत में शामिल होकर अपने मामलों का समाधान कराने की अपील की है।

पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बंद करने की मांग, ब्यौहारी में भारत आदिवासी पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

मीडिया ऑडीटर, शहडोल (निप्र)। शहडोल जिले के ब्यौहारी में गुरुवार को पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण नीति के विरोध में भारत आदिवासी पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने संयुक्त रूप से सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की एथेनॉल मिश्रण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे तत्काल बंद करने की मांग की धरना समाप्त होने के बाद दोनों दलों के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति से आम वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका दावा है कि

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग से वाहनों का माइलेज प्रभावित हो रहा है और इंजन की कार्यक्षमता पर भी असर पड़ रहा है। धरना स्थल पर संबोधित करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण के कारण वाहनों के रखरखाव का खर्च बढ़ सकता है उन्होंने दावा किया कि दोपहिया और चारपहिया वाहन मालिकों को अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ रहा है कार्यकर्ताओं का कहना था कि ईंधन की गुणवत्ता और वाहन प्रदर्शन में किसी भी प्रकार की कमी का सीधा प्रभाव आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है उन्होंने सरकार से मांग की कि ईंधन नीति बनाते समय आम नागरिकों के हितों को प्राथमिकता दी जाए। प्रदर्शन के बाद भारत आदिवासी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी तहसील कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की वर्तमान व्यवस्था को बंद करने और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने की मांग की गई।

बाल श्रम, बाल विवाह और बाल तस्करी रोकने के लिए सख्त निर्देश

मऊगंज में जिला टास्क फोर्स की बैठक, कलेक्टर ने कहा- शिकायत मिलते ही करें तत्काल कार्रवाई

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। जिले में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला टास्क फोर्स समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर संजय कुमार जैन ने की बैठक में बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम को लेकर विभागवार कार्यों की समीक्षा की गई कलेक्टर ने बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी शिकायत या सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए उन्होंने कहा कि बाल अपराधों की रोकथाम के लिए केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि नियमित निगरानी, जनजागरूकता और विभागों के बीच बेहतर समन्वय भी जरूरी है। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने कहा कि बाल श्रम, बाल विवाह और बाल तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयां बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं इन्हें रोकने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में नियमित निरीक्षण अभियान चलाए जाएं और ऐसे स्थानों की पहचान की जाए जहां बच्चों के शोषण या उनके अधिकारों के उल्लंघन की संभावना हो सकती है उन्होंने कहा कि किसी भी माध्यम से शिकायत मिलने पर संबंधित विभाग बिना देरी किए कार्रवाई करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए।

मिशन वात्सल्य और चाइल्ड हेल्पलाइन की समीक्षा: बैठक में मिशन वात्सल्य, चाइल्ड हेल्पलाइन, किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और बाल कल्याण समिति की गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जरूरतमंद और संवेदनशील बच्चों की पहचान कर उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा का लाभ समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है बैठक में बच्चों के पुनर्वास, संरक्षण और उनके अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि बाल संरक्षण केवल अपराध रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के समग्र विकास से जुड़ा विषय है उन्होंने निर्देश दिए कि चिन्हित बच्चों को स्कूलों से जोड़ा जाए और उन्हें स्वास्थ्य, पोषण तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।

चोरी भी... वापसी भी! आखिर भारत की सांस्कृतिक धरोहरों का प्रहरी कौन?

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

एक ओर दुनिया से लौट रही हैं भारत की बेशकीमती पुरावस्तुएं, दूसरी ओर राज्यों की लापरवाही से देश के भीतर ही असुरक्षित हैं हमारी ऐतिहासिक विरासतें...

भारत इन दिनों अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर दो बिल्कुल विपरीत धाराओं में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली तस्वीर गौरव से भर देने वाली है। दुनिया के बड़े-बड़े संग्रहालयों, निजी संग्रहों और नीलामी घरों में पहुंच चुकी भारत की सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख और कलाकृतियां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चलाए गए पुरा-संपदा वापसी अभियान के तहत एक-एक कर स्वदेश लौट रही हैं, तो दूसरी तस्वीर उतनी ही पीड़ादायक है। वस्तुतः देश के किलों, मंदिरों और संरक्षित स्मारकों से आज भी हमारी अमूल्य धरोहरें और मूर्तियां चोरी हो रही हैं। कई बार प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती, जब तक कि कोई इस बारे में ध्यान नहीं दिलाता है! सवाल यह है कि जब भारत विदेशों से अपनी खोई हुई विरासत वापस लाने में सफल हो रहा है, तब हम अपने ही घर की विरासत को सुरक्षित क्यों नहीं रख पा रहे? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के ऐतिहासिक 'नरवर' किले में हुई घटना ने इस प्रश्न को और अधिक सोचनीय बना दिया है। करीब पांच सौ वर्ष पुरानी, तीन हजार किलोग्राम से अधिक वजनी अष्टधातु की ऐतिहासिक तोप रात के अंधेरे में हथियारबंद बदमाश क्रेन और ट्रक के सहारे उठाकर ले गए। 25 से 30 बदमाशों का गिरोह आया, सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक हथियारों के दम पर धमकाया और सदियों पुरानी धरोहर लेकर चला गया। यह किसी फिल्म की पटकथा नहीं, बल्कि भारत की विरासत सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर है। सबसे अधिक चिंता की बात इस तोप चोरी प्रकरण में यह है कि घटना से पहले संदिग्ध गतिविधियों की सूचना स्थानीय लोगों ने दी थी। सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी हुई थी, किंतु जिम्मेदार तंत्र ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जिस किले में करोड़ों रुपये मूल्य की ऐतिहासिक धरोहर रखी हो, वहां न पर्याप्त रोशनी, न आधुनिक निगरानी व्यवस्था और न प्रशिक्षित सुरक्षा बल! आखिर ऐसी लापरवाही की कीमत कौन चुका रहा है? इतिहास तो पहले ही चुका रहा है, देश के सामने अनेक मसले हैं जो ऐतिहासिक भूल के कारण आज भी भारत के समक्ष नासूर बने हुए हैं! ऐसे में यह घटना सोचने पर विवश कर रही है कि नरवर ही क्यों पिछले कई दशकों से देश के अनेक राज्य अंतरराष्ट्रीय पुरावस्तु तस्करों के लिए आसान निशाना क्यों बने हुए हैं! भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि उसके संरक्षित स्मारकों से ही 480 से अधिक महत्वपूर्ण पुरावशेष गायब हो चुके हैं। सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। तमिलनाडु के चोलकालीन मंदिरों से लेकर बिहार के नालंदा संग्रहालय, कर्नाटक के होयसल मंदिरों, आंध्र प्रदेश के प्राचीन मंदिरों और हिमालयी क्षेत्रों के दुर्लभ देवस्थानों तक, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां तस्करों ने अपनी पहुंच न बनाई हो। खजुराहो की दुर्लभ मूर्तियां हों, तंजावुर के मंदिरों की कांस्य नटराज प्रतिमाएं, चंद्रकेतुगढ़ की मौर्यकालीन टेराकोटा कलाकृतियां या मथुरा की कुषाणकालीन प्रतिमाएं, आज भी भारत की हजारों अमूल्य धरोहरें वर्षों तक फर्जी दस्तावेजों के सहारे विदेशों के संग्रहालयों और निजी संग्रहों तक पहुंचती रही हैं।

संपादकीय

रंगभेद की जंजीर तोड़ने वाला अमर योद्धा

योगेश कुमार गोयल

नेल्सन मंडेला- एक ऐसा नाम, जो समस्त विश्व समुदाय के लिए मानवता, साहस, सहिष्णुता और संघर्ष का प्रतीक बन गया है। प्रतिवर्ष 18 जुलाई को 'नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस' मनाया जाता है, जो न केवल इस महान नेता को श्रद्धांजलि देने का दिन है बल्कि यह पूरी दुनिया को यह संदेश भी देता है कि परिवर्तन लाने के लिए केवल शब्द नहीं बल्कि कर्म आवश्यक हैं। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए हम सभी की भूमिका होती है और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के म्वेजो नामक गांव में हुआ था। वे थेम्बू कुल की एक शाखा मदिवा जनजाति से थे और उनका मूल नाम 'रोहिलाहला मंडेला' था, जिसका अर्थ होता है शरारती। उन्हें 'नेल्सन' नाम उनके स्कूल शिक्षक ने अंग्रेजी नामों की परंपरा के तहत दिया। उनका जीवन एक सामान्य अफ्रीकी बच्चे की तरह शुरू हुआ लेकिन उनके भीतर असाधारण नेतृत्व क्षमता और अन्याय के प्रति गहरी संवेदना थी, जिसने उन्हें बाद में एक क्रांतिकारी नेता बना दिया। नेल्सन मंडेला की शिक्षा की शुरुआत क्लार्कबरी मिशनरी स्कूल से हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी और जोहान्सबर्ग स्थित विटवाटरस्रैंड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने रंगभेद नीति और सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी थी। दक्षिण अफ्रीका में उस समय श्वेत अल्पसंख्यक सरकार द्वारा 'अपरथाइड' नामक नस्लीय भेदभाव की क्रूर नीति लागू थी, जिसके अंतर्गत अश्वेतों को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया था। उन्हें वोट देने, जमीन रखने, शिक्षा प्राप्त करने, अस्पतालों में इलाज करवाने और बसों-रेस्तरां जैसी सार्वजनिक सेवाओं का समान उपयोग करने का अधिकार नहीं था। मंडेला ने इन्हीं नीतियों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया। वे 1944 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए और जल्द ही संगठन के युवा विंग के संस्थापक बन गए। अहिंसा और शांतिपूर्ण आंदोलनों के जरिये उन्होंने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया लेकिन जब उन्हें लगा कि सरकार की दमनकारी नीति अहिंसात्मक विरोध को कुचलने पर आमादा है तो उन्होंने 'उमखोंतो वे सिजवे' नामक एक सशस्त्र संगठन की स्थापना की, जो दक्षिण अफ्रीका में क्रांति का आरंभ था। 1962 में मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर देशद्रोह, हिंसा भड़काने और विदेशी सहायता प्राप्त करने के आरोप लगाए गए। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन्होंने अपना अधिकांश समय कुख्यात रोबेन द्वीप की जेल में बिताया। यह सजा कुल 27 वर्षों की लंबी यातना बन गई परंतु जेल की कोठरी में रहते हुए भी मंडेला की आत्मा आजाद रही। वे न टूटे, न झुके और न डरे। जेल में उन्होंने पढ़ाई की, दूसरे कैदियों को शिक्षित किया और अपना संघर्ष जारी रखा। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका और दुनियाभर में मंडेला की रिहाई की मांग उठने लगी। अंततः सरकार झुकी और 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा किया गया। यह क्षण इतिहास में आज भी जीवंत है, जब एक अश्वेत नेता, जिसे वर्षों तक आतंकवादी करार दिया गया था, अब स्वतंत्रता और न्याय का प्रतीक बन चुका था। रिहाई के बाद मंडेला ने अपने सभी विरोधियों को माफ कर दिया। उन्होंने न केवल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को फिर से संगठित किया बल्कि देश को भी एकजुट किया। उन्होंने विभाजन नहीं बल्कि मेल-मिलाप की राजनीति की। उनकी इसी दूरदृष्टि और अहिंसा के पथ पर अडिग रहने की प्रेरणा ने दक्षिण अफ्रीका को नस्लीय संघर्ष से निकालकर लोकतंत्र की ओर अग्रसर किया। दक्षिण अफ्रीका में 1994 में पहली बार बहुजातीय आम चुनाव आयोजित हुए, जिसमें हर नागरिक को मतदान का अधिकार मिला और परिणामस्वरूप नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। यह महज एक राजनीतिक जीत नहीं थी, यह एक युग परिवर्तन था। मंडेला ने अपने राष्ट्रपतिकाल में सुलह, सामाजिक समरसता और आर्थिक पुनर्निर्माण की नीति को अपनाया। उन्होंने जातीय द्वेष के बजाय सहयोग को बढ़ावा दिया।

किसान और गांव को आत्मनिर्भर बनाने की

मनोज कुमार मिश्र

अस्सी के दशक के आखिर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का कम पढ़े-लिखे और खांटी किसान चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत की अगुवाई में भारतीय किसान यूनियन के नाम से अराजनैतिक एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जिससे लखनऊ और दिल्ली की सरकारें हिल गई। विभिन्न कारणों से वह आंदोलन कुछ सालों में कमजोर होकर दम तोड़ दिया। जिन सवालों पर वह आंदोलन शुरु हुआ और उसे भारी समर्थन मिला, वे सवाल आज भी वहीं खड़े हैं। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अपने शासन के 12 साल में समाज के हर वर्ग के साथ गांव और किसान को आत्मनिर्भर बनाने के हर प्रयास किए हैं। किसान हित में 2021 में तैयार किए तीन कानून विपक्ष के सुनियोजित विरोध के चलते भारी बहुमत होते हुए किसान हित में वापस लिया। इतना ही नहीं हर साल इसमें नई योजनाओं को शामिल करके और बेहतर काम किए जा रहे हैं। चौधरी टिकैत अपने आंदोलन को अराजनैतिक मानते हुए भी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को अपना आदर्श मानते थे। आंदोलन के दौरान कुछ बातें दोहराते रहते थे। उसका उल्लेख जरूरी है। वे कहते थे कि किसान अकेली ऐसी कौम है जो ज्यादा उत्पादन करके भी रोती है और कम उत्पादन करके भी। कम उत्पादन में लागत नहीं निकली और ज्यादा उत्पादन में सही दाम नहीं मिलता। उसी तरह हर उत्पादन करने वाला अपने उत्पाद का दाम खुद तय करता है लेकिन किसान के दाम को वे तय करते हैं, जिन्होंने जीवन में कभी खेती की नहीं। वे चौधरी चरण सिंह के मुख्यमंत्री रहते यानी 1967 में जितने गेहूं या गन्ना में जितना सोना मिलता था, उससे थोड़ा कम दाम तय करने की मांग करते रहे। किसानों की माली हालत सुधारने का यह एक फार्मूला तो यह हो सकता है लेकिन पूरा समाधान इससे भी नहीं हो सकता है। अब हालात बदल गए हैं। सरकार ने गांवों को समृध बनाने के लिए देश के सालाना बजट में भारी बढ़ोतरी की। 2014 में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार केन्द्र में आने से पहले कृषि का बजट 27,663 करोड़ रुपये था, अब वह बढ़कर 1 लाख 40 हजार करोड़ हो चुका है। आज भी देश के 81 करोड़ लोगों को हर महीने फ्री अनाज दिया जा रहा है। सरकार के प्रयास से 58 करोड़ जन-धन खाता खुला है। चार करोड़ पक्के मकान बने। 12 करोड़ शौचालय बने। 16 करोड़ घरों में नल से जल दिया गया। 11 करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। किसान सम्मान निधि के तहत 4.3 लाख करोड़ रुपये दिए गए। 22 फसलों के समर्थन मूल्य में 71 फीसदी की बढ़ोतरी की गई। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना(मनरेगा) अब वीबी जीरामजी योजना बन गई है। उस योजना में 26 करोड़ लोग पंजीकृत हैं, जिन्हें 125 दिन का रोजगार दिया जाता है। हर तरह के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। यूरिया पर 90 फीसदी सब्सिडी दी गई है। फसल बीमा योजना लागू की गई है। किसानों को आसानी से कर्ज दिलवाने की व्यवस्था की गई हैं। सिंचाई के साधन बढ़े हैं। किसानों और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी योजनाओं की लंबी सूची है। बावजूद इसके ने तो निचले स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार कम हुआ और न ही गांवों से पलायन रुका। सरकार ने लाभार्थियों का बैंक खाता खुलवाकर सीधे पैसा उसके खाते में भेजने का इंतजाम किया तो भ्रष्टाचार करने वाले बाहर से ही सौदेबाजी करने लगे। एक ही शौचालय के साथ अनेक फोटो खिंचवाकर कमीशन देकर भुगतान पाने लगे। इस भ्रष्टाचार के चलते बिना रिश्वत कम ही आवास बने और दूसरी सुविधाएं लोगों को दी गई। मनरेगा का भ्रष्टाचार तो पहले से ही जग जाहिर है। भाजपा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) की सरकार के प्रयास से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, उसमें कमी आई है। इन सभी से बड़ी समस्या बार-बार मानसून का धोखा देना और फसल की सरकार से सही मायने में खरीद की गारंटी न मिलना है। इस बार फिर बरसात दगा दे रही है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि में कम बरसात होने से धान की रोपाई देरी से हो रही है। इतना ही नहीं वही किसान रोपाई कर पा रहे हैं, जो सक्षम हैं। यानी जिनके परिवार का कोई और व्यवसाय है या परिवार में कोई नौकरी पेशा है। कम बरसात से दलहन और कपास की खेती पर भी असर पड़ा है। यही हाल सब्जियों का है। सरकार के प्रयास और दावों के बावजूद कब तक देश भर के किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अपनी फसल का लाभप्रद मूल्य मिलेगा। कब तक किसानी का काम लाभकारी बन जाएगा और बेकारी, भुखमरी और गरीबी के चलते गांवों से होने वाला पलायन कम होगा। मनरेगा के चलते तमाम भ्रष्टाचार होते हुए बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिले और कोरोना संकट के दौरान बंटे बड़े पैमाने पर चावल-गेहूं से भुखमरी रुकी। सरकार को यह योजना ज्यादा उपयोगी लगी, इसलिए इसे अब तक जारी रखा गया है। गांव में रहने वाले खेतिहर मजदूरों की समस्या अलग तरह की है। सरकारी योजनाओं का उन्हें भले ही भ्रष्टाचार के चलते पूरा लाभ भले ही नहीं मिलता है लेकिन उससे उनके आर्थिक हालात में कुछ सुधार हुआ है। बड़ी तादाद में खेतिहर मजदूरों ने अपेक्षाकृत संपन्न राज्यों में मजदूरी करके अपनी आर्थिक हालात में सुधार किया। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अब वीबी जीरामदी के बजट में हर साल बढोतरी हो रही है। इस योजना का इस साल का बजट 1.50 लाख करोड़ सालाना तय किया गया है। बड़ा संकट छोटे किसानों के लिए है, जिनके लिए खेती जानलेवा बनती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार देश के 85 फीसद से ज्यादा किसानों के पास ढ़ाई एकड़ से कम जमीन है। इन किसानों पर सरकारी योजनाओं का ज्यादा फोकस होना चाहिए। देश के सात लाख से ज्यादा गांवों को यही किसान आबाद किए हुए हैं। इन्हीं के बूते कोरोना संकट के दौरान भी देश में अन्न की कमी नहीं हो पाई। विपक्ष के सुनियोजित किसान आंदोलन जिन तीन कृषि कानूनों को खत्म करवाने के लिए शुरू किया गया था उनमें एक कानून मंडियों के बाहर भी उपज बेचने की इजाजत देने से था। दूसरा कानून किसानों को सहकारी खेती की अनुमति देने वाला और तीसरे में अनिवार्य फसलों पर से रोक हटाने का था (1.कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य(संवर्धन व सरलीकरण) कानून-2020,2. कृषक(सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर कानून-2020 और 3. आवश्यक वस्तु(संशोधन) कानून-2020)। सरकार यह समझाती रही कि इन बिलों से किसानों को केवल लाभ ही होगा। उनकी जमीन कोई नहीं ले सकता और मंडियां खत्म नहीं की जाएगी। फसलों को खुले में बेचने की इजाजत दी जाएगी। देश में मंडी और उसमें सक्रिय आढ़तियों की व्यवस्था पंजाब और हरियाणा में ही सबसे मजबूत है। पंजाब से ही कुछ किसानों का जत्था दिल्ली की एक सीमा सिंधु बार्डर पर इन कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए आंदोलन शुरू किया। उनके साथ हरियाणा के किसान भी जुड़े। फिर टिकरी बार्डर और गाजीपुर बार्डर पर आंदोलन चलने लगा। कुछ ही दिनों में आंदोलन सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का सुनियोजित षड़यंत्र बन गया।

11 दौर की बातचीत में समाधान नहीं निकला और सरकार को लगा कि उसे सुनियोजित तरीके से किसान विरोधी साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिलों को वापस लेने की घोषणा की और 2012 के संसद के शीतकालीन सत्र में उसे वापस ले लिया गया। एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) किसानों को दिलाने के लिए किसान संगठनों के साथ कमेटी बनाना तय किया गया। आंदोलन में शुरू से ही जमकर राजनीति होने लगी थी। इसलिए यह आंदोलन भी कामयाब न बन पाया। इस आंदोलन के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार दूसरी बार बहुमत में आ गई। यही हाल चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत की अगुवाई वाली भारतीय किसान यूनियन का हुआ था। वह तभी तक ताकतवर रहा जब तक वह सक्रिय राजनीति से दूर रहा और आंदोलन अहिंसक रहा। वह आंदोलन भी अन्य मुद्दों के अलावा किसानों पर से सीमित इलाके में फसल बेचने पर रोक के विरोध में था। वह आंदोलन तब तक सफल रहा जब तक केवल किसानों का रहा। जैसे ही राजनीतिक दल किसानों का समर्थन पाने के लिए उन्हें अपने पक्ष में करने में लग गए, आंदोलन भटक गया। यहां तक कि चौधरी टिकैत का कैंसर जैसी घातक बीमारी से 2011 में एक तरह से गुमनाम निधन हुआ। वास्तव में अन्य व्यवसाय करने वालों की तरह किसानों को ऊंची कीमत पर अपनी फसल बेचने की आजादी मिलनी ही चाहिए। यह संभव कब और कैसे होगा, इसका जवाब आसान नहीं है। बड़ी समस्या तो ढाई एकड़ से कम जोत वाले देश के 85 फीसद किसानों की है जिनका हर तरह से शोषण होता आया है। उनके पास अपने फसल को मंडी तक ले जाने के साधन नहीं हैं और न ही फसल को कुछ समय तक सुरक्षित रखने के लिए भंडार। वे तो गांव से लेकर मंडी तक आढ़तियों या बिचौलियों के शोषण झेलने को मजबूर हैं। अगर चार-पांच किसान मिलकर किराए की गाड़ी से अपने उत्पाद मंडी में लेकर पहुंच भी जाएं तो वहां सक्रिय बिचौलियों को पता है कि वे विपन्न हैं उनके पास कुछ दिन इंतजार करने के साधन नहीं हैं, तो वे उन्हें किसी भी दाम पर अपने फसल को बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं। इतना ही नहीं उन्हें अगली फसल के लिए पैसों की जरूरत है। उनके घर का हर काम उसी फसल की बिक्री पर निर्भर है। केन्द्र की सरकार इस हालात को बदलने के प्रयास में लगी है। इसीलिए स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी तय करने के लिए समग्र लागत से पचास फीसद जोड़कर दाम तय करने का सुझाव दिया। अभी कुल 23 उत्पादों के लिए ही न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) तय होता है। जबकि बड़ी तादाद में किसान फल, सब्जी, दूध, अंडा, मछली आदि डेयरी उत्पाद का उत्पादन करते हैं। इसलिए अब सरकार को एमएसपी में शामिल उत्पादों की संख्या बढ़ानी चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि यह गारंटी मिलनी चाहिए कि एमएसपी से कम दाम पर खरीदने वाले को सजा मिलेगी। केन्द्र सरकार यह दावा करती रही कि मंडी बंद नहीं हो रही होगी। इसके साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करें कि हर गांव-गांव खरीद केन्द्र काम करेंगे ताकि छोटे किसानों को अपने फसल के वाजिब दाम के लिए दर-दर की ठोकर नहीं खानी पड़े। सही मायने में सभी किसानों की आर्थिक हालत तभी सुधरेगी जब सरकार चौतरफा प्रयास करेगी। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का उपाय कर रही है लेकिन उसका पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंकों से सस्ते दर पर कर्ज मिलने की व्यवस्था, कृषि उत्पाद को देश के विभिन्न इलाकों में पहुंचाने के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाने आदि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे छोटे किसानों को काफी मदद मिल रही है। सबसे बड़ी समस्या इन योजनाओं का हर जरूरतमंद तक पहुंचाने और कृषि क्षेत्र में उन प्रयासों को करने से है जिससे किसानों की आमदनी बढ़े। कृषि उत्पाद से जुड़े लाभकारी उद्योगों को गांव-गांव तक पहुंचाने की है। सरकार प्रयास तो कर रही है लेकिन यह काम बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है।

(

आत्मनिर्भर भारत से वैश्विक प्रौद्योगिकी नेतृत्व की ओर एक निर्णायक कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम(स्क्स्स्) को मंजूरी दिया जाना भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक और दूरगामी महत्व का निर्णय है। 62,500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान वाली यह योजना केवल मोबाइल फोन निर्माण बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान, डिज़ाइन और नवाचार का अग्रणी केंद्र बनाना है। यह योजना ऐसे समय में लाई गई है, जब बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए लागू उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (क्स्ह्र-रुस्श्वस्) 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुकी है। नई योजना उस सफलता को अगले चरण तक ले जाने का प्रयास है।

विनोद कुमार सिंह 'तकियावाला'

इसका कार्यकाल वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पाँच वर्षों का होगा।एमपीएमएस के अंतर्गत भारत में निर्मित मोबाइल फोन की पात्र बिक्री पर 2.25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। यदि निर्माता प्रमुख पुर्जों और उप-असेंबलियों की घरेलू खरीद बढ़ाते हैं तो उन्हें 1.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं भारतीय ब्रांडों को डिज़ाइन, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि सरकार केवल असेंबली आधारित उत्पादन नहीं, बल्कि वास्तविक तकनीकी क्षमता, नवाचार और बौद्धिक संपदा निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहती है।सरकार का अनुमान है कि योजना की अवधि में देश में लगभग 39 लाख करोड़ रुपये मूल्य के मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन होगा। साथ ही मोबाइल फोन निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर इससे

कहीं अधिक होंगे, जिससे लाखों युवाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।पिछले एक दशक में 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2014-15 की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लगभग सात गुना तथा निर्यात ग्यारह गुना बढ़ चुका है। आज भारत मात्रा के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है और देश में उपयोग होने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन भारत में ही निर्मित हो रहे हैं।वर्ष 2025 में स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन गया, जिसने डीजल ईंधन और कटे-तराशे हीरों जैसे पारंपरिक निर्यात उत्पादों को भी पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र अब भारतीय अर्थव्यवस्था की नई विकास धुरी बनता जा रहा है।नई योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें भारतीय कंपनियों को अपने स्वयं के ब्रांड, डिज़ाइन और अनुसंधान विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया है।लंबे समय तक भारत वैश्विक कंपनियों के लिए विनिर्माण केंद्र बना रहा, लेकिन अब लक्ष्य केवल निर्माण नहीं, बल्कि तकनीकी स्वावलंबन, भारतीय पेटेंट और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय ब्रांड तैयार करना है।घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाने पर विशेष बल देने से मोबाइल फोन उद्योग में चिप,कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले,बैटरी,प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और अन्य महत्वपूर्ण पुर्जों के निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और आपूर्ति श्रृंखला अधिक मजबूत तथा सुरक्षित बनेगी।आज वैश्विक कंपनियाँ अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं।ऐसे समय में भारत के पास कुशल मानव संसाधन,विशाल घरेलू बाजार,बेहतर अवसंरचना और अपेक्षाकृत स्थिर नीतिगत वातावरण जैसी महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। एमपीएमएस इन सभी क्षमताओं को एकीकृत करते हुए भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।हालाँकि इस योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घरेलू अनुसंधान एवं विकास, सेमीकंडक्टर निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उद्योग, कौशल विकास और नवाचार को समान गति से आगे बढ़ाया जाए। यदि इन क्षेत्रों में भी निरंतर और लक्षित निवेश हुआ तो भारत केवल मोबाइल फोन का निर्माण ही नहीं करेगा, बल्कि भविष्य की मोबाइल तकनीकों के विकास और निर्यात में भी अग्रणी भूमिका निभा सकेगा।स्पष्ट है कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम केवल एक प्रोत्साहन योजना नहीं,बल्कि भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर, नवाचार-आधारित और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स महाशक्ति बनाने की दीर्घकालिक रणनीति का महत्वपूर्ण आधार है।आने वाले वर्षों में यह योजना भारतीय उद्योग,रोजगार,निर्यात और तकनीकी नेतृत्व को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ, तो यह पहल भारत को केवल दुनिया का बड़ा बाजार ही नहीं, बल्कि दुनिया का विश्वसनीय तकनीकी निर्माता और नवाचार केंद्र भी बना सकती है।

400 साल पुरानी सिंधिया रियासत की ऐतिहासिक तोप चोरी नरवर किले की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल, अंतरराष्ट्रीय एंटीक तस्करी की आशंका

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले स्थित ऐतिहासिक नरवर किले से सिंधिया रियासत की लगभग 400 वर्ष पुरानी दुर्लभ तोप चोरी होने का मामला सामने आया है इस घटना ने प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं करीब 3500 किलोग्राम वजनी इस तोप को चोर सुनियोजित तरीके से किले से लगभग 3000 फीट नीचे उतारकर वाहन में लादकर फरार हो गए प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि वारदात के पीछे अंतरराष्ट्रीय एंटीक तस्करों का हाथ हो सकता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ब्लैक मार्केट में इस तरह की दुर्लभ ऐतिहासिक धरोहरों की कीमत 3 से 5 करोड़ रुपये तक आंकी जाती है जानकारी के अनुसार यह वारदात 15-16 जुलाई की रात हुई बदमाश पूरी तैयारी के साथ किले पहुंचे थे। उन्होंने पहले भारी तोप को गद्दों और रजाइयों में लपेटा ताकि उसे नीचे उतारते समय नुकसान न पहुंचे और आवाज भी न हो इसके बाद बैरिंग लगी विशेष लोहे की ट्रॉली की मदद से तोप को दुर्गम रास्ते से लगभग 3000 फीट नीचे लाया गया वहां पहले से मौजूद एक लोडिंग वाहन में तोप को रखकर आरोपी फरार हो गए घटनास्थल पर भारी वाहनों के टायरों के निशान और अन्य कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं।

10 दिन पहले भी हुई थी चोरी की कोशिश: जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि चोरों ने इस वारदात की योजना काफी पहले बना ली थी। 4 से 5 जुलाई की रात भी बदमाशों ने इसी तोप को उसके मूल स्थान से नीचे गिरा दिया था लेकिन अत्यधिक वजन होने के कारण वे उसे वहां से ले जाने में सफल नहीं हो सके उस समय सुरक्षा गार्डों ने नरवर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। माना जा रहा है कि यदि उस शिकायत पर समय रहते कार्रवाई होती तो यह ऐतिहासिक चोरी टाली जा सकती थी।

अब किले में बचीं केवल 13 ऐतिहासिक तोपें: नरवर किले की ओपन कचहरी में पहले सिंधिया राजवंश काल की कुल 14 ऐतिहासिक तोपें रखी थीं चोरी के बाद अब वहां केवल 13 तोपें शेष रह गई हैं चोरी हुई तोप की लंबाई लगभग 5 फीट 10 इंच और चौड़ाई करीब 30 इंच बताई गई है यह तोप पीतल, तांबा, कांसा और अष्टधातु जैसी मिश्रित धातुओं से निर्मित थी जिस पर फारसी और देवनागरी लिपि में ऐतिहासिक शिलालेख भी अंकित थे विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार की तोपें केवल सैन्य इतिहास ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

नरवर किले का ऐतिहासिक महत्व: नरवर किले का इतिहास कई शताब्दियों पुराना है किले की कचहरी महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में कछवाहा राजाओं द्वारा कराया गया था बाद में वर्ष 1925 में महाराजा माधवराव सिंधिया के आदेश पर इसका जीर्णोद्धार कराया गया यहां संरक्षित तोपें सिंधिया शासनकाल की सैन्य शक्ति और धातु कला का महत्वपूर्ण प्रमाण मानी जाती हैं इनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के कारण देश-विदेश के शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए भी इनका विशेष महत्व है।

सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही: घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल किले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहा है जानकारी के अनुसार नरवर किले की सुरक्षा के लिए कुल छह गार्ड नियुक्त हैं इनमें चार गार्ड दिन में और दो गार्ड रात में ड्यूटी करते हैं घटना वाली रात दोनों रात्रि गार्ड अपने-अपने घर चले गए थे जिससे पूरा किला बिना सुरक्षा के रह गया।

सुरक्षा गार्ड बालकिशन बाल्मीक ने स्वीकार किया कि किले में रात में रुकने की उचित व्यवस्था नहीं है। वहां न तो पर्याप्त रोशनी है और न ही टॉर्च या अन्य सुरक्षा संसाधन उपलब्ध हैं इसी कारण वह रात में घर चला गया था वहीं दूसरे गार्ड शरणलाल जाटव ने भी माना कि घटना के समय वह ड्यूटी पर मौजूद नहीं था।

चिरमिरी में श्रद्धा और उल्लास के साथ निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। एमसीबी जिले के चिरमिरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा गुरुवार को पूरे धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ निकाली गई इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए और पूरा शहर 'जय जगन्नाथ' के जयघोष से गूंज उठा भजन-कीर्तन, पुष्पवर्षा और प्रसाद वितरण के बीच चिरमिरी का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया रथयात्रा की शुरुआत चिरमिरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से हुई, जिसे ओडिशा के प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन माता सुभद्रा के विग्रहों को आकर्षक ढंग से सजे रथ में विराजमान कर विधि-विधान और पूजा-अर्चना के बाद नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया यात्रा का सबसे भावुक और आकर्षक दृश्य तब देखने को मिला, जब हजारों श्रद्धालु भगवान के रथ की रस्सी खींचने के लिए उमड़ पड़े धार्मिक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचने से पुण्य की प्राप्ति होती है और श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इसी आस्था के साथ महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे बड़ी संख्या में रथयात्रा में शामिल हुए रथयात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारी, पुष्पवर्षा की और प्रसाद का वितरण किया भक्ति गीतों और जयघोष से पूरा शहर आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया आयोजन समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्रसाद और अन्य आवश्यक सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई थी यात्रा के दौरान स्वयंसेवकों ने व्यवस्था संभालते हुए श्रद्धालुओं की सहायता की वहीं पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चैनपुर में करियर काउंसलिंग, बालिकाओं को मिला उज्ज्वल भविष्य का मार्गदर्शन

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। भारत सरकार की महत्वाकां बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत युवा कौशल दिवस के अवसर पर शासकीय माध्यमिक शाला चैनपुर में आयोजित दो दिवसीय करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा, करियर, रोजगार, कौशल विकास और विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनने के लिए प्रेरित करना था कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने भविष्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। यह आयोजन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संतन देवी जांगड़े के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सहयोग से किया गया कार्यक्रम का संचालन जिला महिला सशक्तिकरण (हब) मिशन शक्ति की जिला मिशन समन्वयक तारा कुशवाहा ने किया। करियर काउंसलिंग सत्र के दौरान छात्राओं को उनकी रुचि, क्षमता और लक्ष्य के अनुरूप विषय चयन, उच्च शिक्षा के अवसर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, रोजगार के क्षेत्र और विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई विशेषज्ञों ने बताया कि सही दिशा में की गई तैयारी और निरंतर मेहनत से ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाएं भी अपने सपनों को साकार कर सकती हैं साथ ही उन्हें कौशल विकास कार्यक्रमों और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण की उपयोगिता से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम में जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र की जेंडर विशेषज्ञ शैलजा गुप्ता, वित्तीय साक्षरता समन्वयक अनीता कुमारी साह तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पीएलवी अंजनी यादव ने विभिन्न शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने नोनी सुरक्षा योजना, सक्षम योजना, सखी निवास, शक्ति सदन, नारी अदालत, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, चाइल्ड हेल्पलाइन और नवा बिहान जैसी योजनाओं के लाभ एवं पात्रता के बारे में जानकारी साझा की इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकार, सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता और कानूनी सहायता से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी जागरूक किया गया।

सेंट्रिंग प्लेट व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनीं फूलकली, बिहान मिशन ने दी आर्थिक सशक्तिकरण की नई पहचान

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान-एनआरएलएम) ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार सफल प्रयास कर रहा है। इसी मिशन से जुड़कर विकासखंड भरतपुर के ग्राम डोंगरीटोला की फूलकली ने स्वरोजगार के माध्यम से न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत की बल्कि क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का उदाहरण प्रस्तुत किया है सेंट्रिंग प्लेट व्यवसाय के जरिए वे आज नियमित आय अर्जित कर आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीवनयापन कर रही हैं फूलकली अनामिका महिला स्व-सहायता समूह की सक्रिय सदस्य हैं। 4 अक्टूबर 2019 को गठित इस समूह में 10 महिलाएं शामिल हैं। बिहान मिशन की विकासखंड मिशन प्रबंधन इकाई के मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सतत क्षमता विकास कार्यक्रमों ने समूह की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया एक साधारण गृहिणी के रूप में जीवन शुरू करने वाली फूलकली ने भी समूह से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया समूह की बैठकों में नियमित भागीदारी और अनुशासित कार्यशैली के कारण उन्हें सबसे पहले रिवॉल्विंग फंड से 15 हजार रुपये का ऋण प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने परिवार की आवश्यक जरूरतों को पूरा किया। इसके बाद समूह को सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) के तहत 60 हजार रुपये की सहायता मिली इस आर्थिक सहयोग ने उनके जीवन की दिशा बदल दी उन्होंने अपनी बचत और उपलब्ध संसाधनों को मिलाकर लगभग एक लाख रुपये का निवेश किया और सेंट्रिंग प्लेट व्यवसाय की शुरुआत की।

व्यवसाय के शुरुआती दौर में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने अपने कारोबार को सफल आज उनका सेंट्रिंग प्लेट व्यवसाय सुचारु रूप से संचालित हो रहा है इस व्यवसाय से उन्हें प्रतिमाह लगभग 10 हजार रुपये की नियमित आय प्राप्त हो रही है जबकि वार्षिक रूप से करीब 1.20 लाख रुपये का लाभ अर्जित हो रहा है इस आय से उन्होंने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की है, घरेलू जरूरतों को सहजता से पूरा किया है और भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की है फूलकली की सफलता अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी है।

नैनो डीएपी ने बदली किसान इंद्रभान सिंह की खेती की तस्वीर, कम लागत में बेहतर उत्पादन की बढ़ी उम्मीद

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। भरतपुर विकासखंड के ग्राम मैनपुर के प्रगतिशील किसान इंद्रभान सिंह कंवर ने आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाकर यह साबित कर दिया है कि वैज्ञानिक सलाह और नई तकनीक के समन्वय से खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है इफको नैनो डीएपी के उपयोग से उन्हें न केवल खेती की लागत कम करने में सफलता मिली बल्कि फसल की गुणवत्ता और विकास में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं उनकी सफलता अब क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है किसान इंद्रभान सिंह कंवर, पिता ललन सिंह कंवर, वर्षों से खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं बढ़ती कृषि लागत और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता उनके लिए चिंता का विषय थी ऐसे समय में कृषि विभाग और सहकारी समिति के मार्गदर्शन में उन्हें इफको नैनो डीएपी की जानकारी मिली। शुरुआत में उनके मन में इस नई तकनीक को लेकर संदेह लेकिन कृषि विशेषज्ञों ने नैनो डीएपी की कार्यप्रणाली, उपयोग की विधि और इसके लाभों के बारे में विस्तार से समझाया विशेषज्ञों ने बताया कि नैनो डीएपी पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है जिससे पोषक तत्वों का अधिक प्रभावी उपयोग होता है और फसल का संतुलित विकास सुनिश्चित होता है वैज्ञानिक सलाह पर भरोसा करते हुए इंद्रभान सिंह ने खरीफ सीजन में अपनी धान की फसल में नैनो डीएपी का उपयोग किया कुछ ही समय बाद उन्हें इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे खेत में पौधों की बढ़वार पहले की तुलना में अधिक समान और स्वस्थ रही फसल में हरियाली बनी रही तथा पौधों का विकास संतुलित रूप से हुआ इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें विश्वास हो गया।

प्रेम प्रसंग से नाराज पिता-पुत्र ने की युवक की हत्या, शव रेलवे ट्रैक पर फेंककर हादसा दिखाने की कोशिश

मीडिया ऑडीटर, छतरपुर (निप्र)। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में प्रेम प्रसंग के चलते हुई एक सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है मातगुवां थाना पुलिस ने पिता और उसके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार किया है आरोप है कि दोनों ने 21 वर्षीय युवक रामजी रैकवार की कुल्हाड़ी से हत्या कर शव को बोरे में भरकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि मामला ट्रेन दुर्घटना जैसा लगे पुलिस के अनुसार 27 जून 2026 को महाराजा छत्रसाल और ईसानगर रेलवे स्टेशन के बीच एक क्षत-विक्षत शव मिला था जांच में मृतक की पहचान ग्राम महेवा निवासी रामजी रैकवार के रूप में हुई, जिसकी गुमशुदगी पहले से दर्ज थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई पूछताछ में आरोपी मूलचंद रैकवार और उसके नाबालिग बेटे ने हत्या की बात स्वीकार कर ली पुलिस के मुताबिक, रामजी का मूलचंद की बेटी से पिछले पांच वर्षों से प्रेम संबंध था और दोनों शादी करना चाहते थे परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था इसी रंजिश में आरोपी ने युवक को खेत पर बुलाया और बेटे के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी।

हत्या के बाद शव को पहले झाड़ियों में छिपाया गया और फिर रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, बाइक और मृतक का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में कार्रवाई की जा रही है।

प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना से साकार हुआ पक्के घर का सपना, सुकवरिया के परिवार को मिला सम्मान और सुरक्षा

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जनपद पंचायत खड़गवां के ग्राम नेवरी की निवासी सुकवरिया के जीवन में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना ने नई उम्मीद और खुशियों का संचार किया है। वर्षों तक कच्चे और जर्जर मकान में कठिन परिस्थितियों के बीच जीवन बिताने वाले इस परिवार को अब योजना के तहत पक्का आवास मिल गया है सुरक्षित और मजबूत घर मिलने से उनके परिवार के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है तथा भविष्य को लेकर नई उम्मीद जगी है सुकवरिया और उनके पति पन्नूलाल लंबे समय से आर्थिक तंगी के कारण पक्का घर नहीं बना पा रहे थे। उनका परिवार एक कच्चे मकान में रहता था जहां हर मौसम अपने साथ नई परेशानियां लेकर आता था। बरसात में छत टपकती थी, गर्मियों में तेज गर्मी और सर्दियों में ठंडी हवाओं से परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था हर वर्ष बारिश के मौसम में मकान के क्षतिग्रस्त होने का डर बना रहता था जिससे परिवार हमेशा चिंता में रहता था इसी दौरान प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना उनके जीवन में परिवर्तन का माध्यम बनकर पात्रता के आधार पर उन्हें योजना का लाभ मिला और शासन से आर्थिक सहायता प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपने सपनों का पक्का घर बनवाया आज उनका परिवार मजबूत और सुरक्षित आवास में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है सुकवरिया बताती हैं कि नया घर मिलने के बाद उनके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं अब बारिश के दिनों में छत टपकने की चिंता नहीं रहती और न ही आंधी-तूफान का भय सताता बच्चों को पढ़ाई के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण मिला है जबकि पूरे परिवार को स्वच्छ, व्यवस्थित और बेहतर रहन-सहन का लाभ प्राप्त हो रहा है। पक्का घर मिलने से परिवार के भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ा है और सामाजिक सम्मान में भी वृद्धि हुई है वे कहती हैं कि पहले हर मौसम उनके लिए चिंता का कारण बन जाता था लेकिन अब उनका परिवार निश्चिंत होकर अपने घर में रह रहा है यह घर केवल चार दीवारों का निर्माण नहीं बल्कि उनके परिवार के सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की मजबूत नींव है उनके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ झलकती है।

रिहायशी इलाके में प्रस्तावित शराब दुकान का विरोध तेज, मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेस और वार्डवासियों ने आबकारी विभाग को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ शहर में वार्ड क्रमांक-16 के रिहायशी क्षेत्र में प्रस्तावित शराब दुकान को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में वार्डवासियों ने आबकारी विभाग पहुंचकर ज्ञापन सौंपा उन्होंने मांग की कि आबादी के बीच शराब दुकान खोलने की योजना तत्काल निरस्त की जाए और दुकान को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि रिहायशी इलाके में शराब दुकान खुलने से क्षेत्र का सामाजिक वातावरण प्रभावित होगा उन्होंने आशंका जताई कि इससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है स्थानीय लोगों के अनुसार जिस स्थान पर शराब दुकान प्रस्तावित है उसके आसपास बड़ी संख्या में परिवार निवास करते हैं और रोजाना महिलाओं, बच्चों तथा विद्यार्थियों का आना-जाना रहता है ऐसे में वहां शराब दुकान खोलना जनहित के खिलाफ होगा। कांग्रेस और वार्डवासियों द्वारा आबकारी विभाग को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि शराब दुकान खुलने से क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों के बढ़ने की आशंका रहेगी सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, विवाद, शोर-शराबा और कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लोगों का कहना है कि इससे न केवल स्थानीय निवासियों का दैनिक जीवन प्रभावित होगा बल्कि बच्चों और युवाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ज्ञापन में प्रशासन से आग्रह किया गया कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए प्रस्तावित दुकान के लिए किसी ऐसे स्थान का चयन किया जाए जहां आबादी कम हो और आम नागरिकों को असुविधा न हो । कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि पार्टी स्थानीय नागरिकों की भावनाओं के साथ खड़ी है उन्होंने कहा कि किसी भी रिहायशी क्षेत्र में शराब दुकान खोलने का निर्णय लेने से पहले स्थानीय लोगों की राय लेना आवश्यक है यदि बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो प्रशासन को उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए उन्होंने आरोप लगाया कि आबादी वाले इलाके में शराब दुकान खोलने का फैसला स्थानीय हितों के अनुरूप नहीं है प्रशासन को चाहिए कि वह प्रस्तावित स्थान पर दुकान खोलने की प्रक्रिया तत्काल रोके और वैकल्पिक स्थान की तलाश करे। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं और स्थानीय नागरिकों ने कहा कि उनके क्षेत्र में पहले से ही परिवारों की बड़ी आबादी रहती है यदि यहां शराब दुकान खुलती है तो महिलाओं और छात्राओं को आवागमन में असुरक्षा महसूस हो सकती है लोगों का कहना है कि शराब दुकान के आसपास भीड़ जुटने, नशे में विवाद होने और सामाजिक शांति भंग होने जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। स्थानीय नागरिकों ने यह भी कहा कि बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है उनका मानना है कि शिक्षा और पारिवारिक वातावरण वाले क्षेत्र में शराब दुकान की स्थापना उचित नहीं है।

नर्मदापुरम में कांग्रेस नेता की कमर्शियल बिल्डिंग के बाथरूम में युवक का शव मिला

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में गुरुवार रात कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष फैजान उल हक की कमर्शियल बिल्डिंग के प्रथम तल स्थित बाथरूम में एक 30 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई मौके से 100 सरकारी सिरिंज का पैक बॉक्स, एक इस्तेमाल की हुई सिरिंज और दवा की एक बोतल बरामद होने के बाद पुलिस कई पहलुओं से मामले की जांच कर रही है शुरुआती जांच में इंजेक्शन के नशे से मौत की आशंका जताई जा रही है हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मौत के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 9 बजे बिल्डिंग के चौकीदार ने देखा कि पहली मंजिल का बाथरूम काफी देर से अंदर से बंद है कई बार आवाज देने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उसने बिल्डिंग मालिक फैजान उल हक को सूचना दी इसके बाद पुलिस को बुलाया गया पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा खोला गया तो अंदर एक युवक का शव जमीन पर पड़ा मिला।

मृतक की पहचान आधार कार्ड के जरिए ओमप्रकाश पिता पूरनलाल ताईया (30), निवासी आदमगढ़ के रूप में हुई वह मजदूरी का काम करता था पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बाथरूम को सील कर दिया।

रतलाम में बड़े भाई ने की भाई की हत्या:शराब के नशे में हुआ विवाद सिर पर किया वार, इलाज के दौरान मौत

मीडिया ऑडीटर, रतलाम (निप्र)। रतलाम के थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मणपुरा में शराब के नशे में दो भाईयों में विवाद में छोटे भाई की मौत हो गई। घायल अवस्था में छोटे भाई को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। जहां से उसे इंदौर रैफर कर दिया। शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत गई। मृतक का नाम विमल महावार (30) है। गुरुवार रात करीब 2 बजे छोटे भाई विमल का बड़ा भाई त्रिलोकचंद से घर में विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर कपड़े धोने की मोगरी से वार कर दिया। इससे उसके सिर पर खून निकलने लगा। रात में शोर-शराबा सुन कर घर में सो रही मां ने आसपास वाले को बुलाया।

रात में ही एंबुलेंस बुलाकर बड़ा भाई त्रिलोक व

रिश्तेदार पवन महावर घायल विमल को लेकर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। जहां हालाक गंभीर होने पर रात में ही इंदौर रेफर कर दिया। सुबह करीब 10 बजे इलाज के दौरान इंदौर में विमल की मौत हो गई।

पुलिस पहुंची घर ताला लगाया: युवक की मौत की सूचना मिलने पर सुबह थाना प्रभारी गायत्री सोनी व पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घर में से सिर पर वार करने वाली मोगरी मिली। घर में खून के धब्बे के निशान भी मिले है। एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुटी।

मां लकवाग्रस्त, छोटा बेटा ध्यान रखता था: घर में दोनों भाई व मां जमनाबाई रहते थे। पिता का काफी सालों पहले निधन हो चुका है। मां भी अधिकतर समय बीमार रहने के कारण छोटा बेटा विमल ही उनकी देखरेख करता था। सुबह तक उन्हें मौत की जानकारी नहीं दी गई। पुलिस ने मां व आसपास वालों से भी पूछताछ कर रही है।

आए दिन होता था विवाद: पड़ोसियों ने बताया कि आए दिन दोनों भाईयों में शराब के नशे में विवाद होता था। बड़ा भाई हमेशा छोटे को मारता था। लेकिन छोटे ने कभी हाथ नहीं उठाया। बड़ा भाई त्रिलोकचंद लोहे के सरिये लगाने का काम करता है जबकि मृतक ढोल बजाता था। दो बहने भी जिनकी शादी हो चुकी है।

थाना प्रभारी गायत्री सोनी ने बताया कि प्राथमिक जांच में शराब के नशे में दोनों भाईयों में विवाद हुआ है। जिसमें छोटे भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इलाज के लिए मृतक का बड़ा भाई भी साथ गया था। इंदौर से आने पर उससे पूछताछ की जाएगी। सारे तथ्यों में ध्यान रख घटनाक्रम की जांच की जा रही है।

दमोह में नवविवाहिता को फिनायल पिलाया, हालत गंभीर

डॉक्टर पति और सास-ससुर पर आरोप, दहेज में 20 लाख की कार के लिए प्रताड़ित किया

मीडिया ऑडीटर, दमोह (निप्र)। दमोह की क्रिश्चियन कॉलोनी में एक वेटरनरी डॉक्टर और उसके माता-पिता पर अपनी 24 वर्षीय नवविवाहिता को फिनायल पिलाने के आरोप लगे है। पीड़ित महिला को गंभीर हालत में शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मायके पक्ष का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले 20 लाख रुपए की कार की मांग को लेकर महिला के साथ मारपीट कर रहे थे।

शादी के तीन महीने बाद ही शुरू हुई प्रताड़ना: जबलपुर के पनागर निवासी पीड़ित महिला की मां पार्वती राय ने बताया कि उनकी बेटी शिवानी की शादी इसी साल 30 अप्रैल को दमोह के वेटरनरी डॉक्टर मनीष राय से हुई थी। शादी में मायके पक्ष ने करीब 30 लाख रुपए खर्च किए थे।

आरोप है कि शादी के तुरंत बाद से ही पति मनीष, ससुर विशाल और सास अनीता दहेज के लिए शिवानी को प्रताड़ित करने लगे थे।

फोन पर दी फिनायल पिलाने की जानकारी: शुक्रवार सुबह शिवानी ने जबलपुर में अपनी मां को फोन कर बताया कि पति और सास-ससुर ने मिलकर उसे जबरन फिनायल पिला दिया है। इसके बाद मां ने दमोह में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को सूचना दी। शिवानी के मौसी का बेटा सोनू राय जब क्रिश्चियन कॉलोनी स्थित घर पहुंचा, तो आरोपी वहां से गायब थे। सोनू ने तुरंत शिवानी को जिला अस्पताल पहुंचाया।

नायब तहसीलदार के सामने दर्ज हुए बयान: घटना की सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार धनीराम सिंह ठाकुर बयान दर्ज करने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि पीड़ित शिवानी के बयान ले लिए गए हैं। शिवानी ने अपने बयानों में पति और सास-ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और फिनायल जैसी कोई जहरीली दवा पिलाने का आरोप लगाया है।

मप्र पर्यटन क्विज-2026 हेतु 25 जुलाई तक किए जा रहे हैं पंजीयन

मीडिया ऑडीटर,रायसेन (निप्र)। मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा प्रदेश के समृद्धशाली इतिहास, परम्पराओं, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विविधताओं, कला, प्राकृतिक समृद्धि, महापुरूषों, पर्यटन महत्व की संभावनाओं आदि से विद्यार्थियों को अवगत कराने तथा पर्यटन के माध्यम से जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 से निरंतर पर्यटन क्विज का आयोजन किया जा रहा है।

इस पर्यटन क्विज का आयोजन प्रदेश के समस्त जिलों में एक साथ, एक ही तिथि को किया जाता है।

स्कूल शिक्षा विभाग के निरंतर सहयोग से यह आयोजन एक उत्सव का रूप ले चुका है। रायसेन जिले में मध्यप्रदेश पर्यटन क्विज-2026 के सफल आयोजन हेतु कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

पर्यटन क्विज-2026 के लिए प्रतिभागी टीम/विद्यालयों का पंजीयन कार्य 01 जुलाई से शुरू हो गया है तथा यह पंजीयन 25 जुलाई तक टूरिज्म बोर्ड की वेबसाईट https//www.tourism.mp.gov.in पर ऑनलाईन किए जा सकते हैं।जिला स्तर पर अधिक से अधिक हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के पंजीयन हेतु अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

आरएके कॉलेज में रोपे गए 01 हजार से अधिक पौधे, 117 विद्यार्थियों और शिक्षकों ने लिया सभी पौधों के संरक्षण का संकल्प

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। आरएके कॉलेज में 'ग्रीन ग्रेजुएशन डिग्री कार्यक्रम' तथा 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के प्रति जागरूकता विकसित करना था। कार्यक्रम में प्रथम वर्ष के 117 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक ग्राफ्टेड किस्मों–केसर, दशहरी एवं राजापुरी सहित अन्य प्रजातियों के लगभग 01 हजार पौधों का रोपण किया तथा प्रत्येक विद्यार्थी ने अपनी डिग्री के पूरे कार्यकाल में पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लिया। इस अवसर पर श्री मनोहर लाल वर्मा, अधिष्ठाता डॉ. एसपी दत्ता, प्रगतिशील किसान डॉ. शिवप्रसाद ठाकुर, श्री दुलीचन्द्र वर्मा, डॉ. डी.आर सक्सेना, डॉ. आई.एस. नरूका, डॉ. डी. के. प्यासी सहित कॉलेज के प्राध्यापकगण, अधिकारी, कर्मचारी एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।

बुरहानपुर में एक घंटे तक रुक-रुक कर बारिश: गर्मी से राहत मिली, सूखे की चिंता के बीच किसानों के चेहरे खिले

मीडिया ऑडीटर, बुरहानपुर (निप्र)। बुरहानपुर शहर में गुरुवार शाम 6:15 बजे के बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, जो शाम 7:15 बजे तक रुक-रुक कर जारी रही। पिछले कुछ दिनों से बारिश न होने के कारण शहर में गर्मी बढ़ गई थी, जिससे आमजन परेशान थे। गुरुवार शाम हुई इस बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले बुधवार को अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस था, जबकि मंगलवार को भी यही स्थिति थी।

अब तक 313.5 मिलीमीटर बारिश: जिले के किसान अपनी बोवनी का काम पूरा कर चुके थे, लेकिन बारिश न होने से वे सूखे की आशंका को लेकर चिंतित थे। गुरुवार शाम की बारिश ने उनकी चिंता कुछ हद तक कम की है। बुरहानपुर जिले में 1 जून से अब तक कुल 313.5 मिलीमीटर (12.3 इंच) बारिश दर्ज की गई है। जिले की सामान्य औसत बारिश 823.6 मिलीमीटर है।

9 दिन से थमा मानसून, किसानों की बढ़ी चिंता:मंदसौर में 19 जुलाई से फिर सक्रिय होने के संकेत, खरीफ फसलों को मिलेगी राहत

मीडिया ऑडीटर, मंदसौर (निप्र)। मंदसौर जिले में मानसून की गति धीमी पड़ गई है। पिछले 9 दिनों से जिले में अच्छी बारिश दर्ज नहीं हुई है। आखिरी बार 8 जुलाई को महत्वपूर्ण वर्षा हुई थी, जिसके बाद 9 जुलाई की रात कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई थी। तब से लेकर शुक्रवार तक जिले में बारिश नहीं हुई है, जिससे पूरा जिला अच्छी वर्षा का इंतजार कर रहा है। बारिश न होने के कारण दिनभर तेज धूप और उमस से लोग परेशान हैं। सुबह से शाम तक गर्मी का असर बना हुआ है। बादल छाते हैं, लेकिन बिना बरसे ही आगे बढ़ जाते हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। इस स्थिति से किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है। जिला मुख्यालय के साथ-साथ नाहरगढ़, भावगढ़, गरोठ, सुवासरा, शामगढ़, दलौदा, मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी, नारायणगढ़, डिगांव, सुंठोद, बरखेड़ा और अफजलपुर सहित जिले के अधिकांश क्षेत्रों में भी कई दिनों से अच्छी बारिश नहीं हुई है। मानसून कमजोर पड़ने से खेतों की नमी कम होने लगी है, जिससे खरीफ फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।

तीन दिन बाद दोबारा सक्रिय होगा मानसून: जिले में अब तक औसतन लगभग 10.10 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। हालांकि, जुलाई के दूसरे सप्ताह में बारिश का लंबा अंतराल किसानों के लिए चिंता का विषय बन गया है। यदि जल्द ही अच्छी बारिश होती है, तो सोयाबीन, मक्का और अन्य खरीफ फसलों को पर्याप्त नमी मिल सकेगी। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल मानसून कमजोर है, लेकिन अगले दो से तीन दिनों में इसके दोबारा सक्रिय होने के संकेत हैं। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और उमस बनी रहेगी।

आगामी दिनों का संभावित मौसम: 18 जुलाईः बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 19 जुलाईः जिले के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 20 से 22 जुलाईः मानसून के दोबारा सक्रिय होने के संकेत हैं। इन दिनों हल्की से मध्यम बारिश के कई दौर आ सकते हैं। तापमान घटकर 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

किसानों और आम लोगों के लिए सलाह: बारिश की संभावना को देखते हुए खेतों में जल निकासी की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करें। बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। तेज बारिश होने की स्थिति में निचले इलाकों में जलभराव की संभावना को देखते हुए सतर्क रहें।फिलहाल जिले में लोग और किसान दोनों अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, 19 जुलाई से मानसून के दोबारा सक्रिय होने के बाद जिले में रुक-रुक कर बारिश और गरज-चमक का दौर शुरू हो सकता है।

सिवनी मालवा में एक हफ्ते से बारिश नहीं: धान की फसल सूखने की कगार पर; किसान बोले-उपज पर पड़ेगा असर

मालवा मीडिया ऑडीटर,सिवनी(निप्र)। सिवनी मालवा तहसील क्षेत्र में एक सप्ताह से अधिक समय से बारिश न होने के कारण धान की फसल संकट में है।

तेज धूप और उमस से खेतों की नमी तेजी से खत्म हो रही है, जिससे धान की फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है। बारिश का इंतजार कर रहे किसान अब चिंतित हैं।

ग्राम सूरजपुर के किसान शेखर रघुवंशी ने बताया कि उन्होंने इस वर्ष करीब 18 एकड़ में धान की फसल लगाई है। शुरुआती दौर में अच्छी बारिश से फसल की बढ़वार बेहतर थी, लेकिन पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से बारिश न होने के कारण खेतों की मिट्टी सूखने लगी है। लगातार तेज गर्मी से खेतों में दरारें पड़ रही हैं और धान के पौधे मुरझा रहे हैं।

रघुवंशी के अनुसार, यदि जल्द बारिश नहीं हुई तो फसल को भारी नुकसान हो सकता है। धान की खेती में प्रति एकड़ लगभग 20 हजार रुपये का खर्च आता है। फसल सूखने की स्थिति में किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

क्षेत्र के अन्य किसानों का कहना है कि धान की फसल को इस समय सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। बारिश में लगातार देरी से फसल की वृद्धि प्रभावित हो रही है।

किसानों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि यदि जल्द बारिश नहीं होती है, तो फसल की स्थिति का सर्वे कराया जाए और नुकसान होने पर उचित राहत व मुआवजा दिया जाए।

मौसम की बेरुखी ने सिवनी मालवा तहसील के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सभी किसान अब आसमान की ओर देख रहे हैं और अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं।

शराब दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट के दो आरोपी गिरफ्तार

रंजिश में गढ़ाकोटा से आकर शराब दुकान पर किया था हमला, मुख्य आरोपी फरार

मीडिया ऑडीटर, सागर (निप्र)। सागर के गौरझामर में शराब दुकान पर तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों से थाने में पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। मामले का मुख्य आरोपी समेत चार अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार, 13 जुलाई की रात नकाबपोश बदमाश शराब दुकान में घुस गए थे। उन्होंने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और दुकान के बाहर खड़ी बाइकों में भी तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इस मामले में छह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने शराब दुकान के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में मारपीट और तोड़फोड़ की घटना कैद मिली। इसके आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू की गई।

ठेकेदार से था विवाद: पुलिस ने जांच के दौरान गढ़ाकोटा निवासी मनीष रैकवार और शुभम नामदेव को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि मुख्य आरोपी रामजी का शराब ठेकेदार मनीष लोधी से पुराना विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में वह अन्य लोगों को साथ लेकर वारदात करने आया था। गौरझामर थाना प्रभारी नासिर फारुखी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यातायात व्यवस्थाओं की कलेक्टर ने की समीक्षा

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनाने तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई। बैठक में एसपी श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना ने भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिले की सड़कों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सड़कों के गड्ढों की मरम्मत नहीं होने पर नगर पालिका सीहोर के सीएमओ को फटकार लगाते हुए तत्काल गड्ढे भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क की खराब स्थिति दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बनती है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही कैशलेस उपचार सुविधा का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद पात्र घायलों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार त्वरित उपचार उपलब्ध कराया जाए तथा मृतक एवं घायलों को मिलने वाली राहत राशि के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए। बैठक में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमित चालानी कार्रवाई, गंभीर मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई, दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स के सुधार, ओवरस्पीडिंग पर प्रभावी नियंत्रण तथा हाईवे पर नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। साथ ही राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया गया। कलेक्टर और एसपी ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने, यातायात बाधित करने वाले अतिक्रमण हटाने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

रोजगार मेले में 388 युवाओं का हुआ प्रारंभिक चयन

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 22 लाख रूपये से अधिक का ऋण वितरित

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सीहोर स्थित महिला आईटीआई कॉलेज में युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया गया। रोजगार मेले में कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा युवाओं का इंटरव्यू लिया गया तथा योग्यता अनुसार चयन किया गया। रोजगार मेले में कुल 418 युवक-युवतियों ने पंजीयन कराया। मेले में कुल 10 कंपनियों द्वारा कुल 388 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया। मेले में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्?गम उन्नयन योजना के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग और पशुपालन विभाग द्वारा 04 हितग्राहियों को 22 लाख 90 हजार रूपये का ऋण वितरित किया गया। रोजगार मेले के शुभारंभ अवसर पर एलडीएम श्री जगदीप भट्टाचार्य, डीआईसी महाप्रबंधक श्री अनुराग वर्मा, जिला रोजगार अधिकारी श्री कमलेश पटेल, प्रबंधक श्री संदीप उईके, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज प्रभारी प्राचार्य डॉ शीलचंद गुप्ता, आईटीआई प्राचार्य श्री गब्बू परमार, श्री विवेक यादव सहित युवा उपस्थित थे।

सीहोर में 9 दिन से थमा मानसून, किसान चिंतित :मौसम विभाग ने 20 जुलाई से बारिश की वापसी का अनुमान जताया

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। सीहोर जिले में पिछले नौ दिनों से मानसून की बेरुखी बनी हुई है। लगातार बारिश नहीं होने से उमस और गर्मी बढ़ गई है, जबकि खेतों में खड़ी खरीफ फसलों को पानी की सख्त जरूरत महसूस होने लगी है।

इसके बावजूद किसान बोनी के बचे हुए कार्य पूरे करने में जुटे हैं और अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने राहत भरा पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार, 20 और 21 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय हो सकता है, जबकि 22 से 24 जुलाई के बीच जिले में अच्छी बारिश होने की संभावना है।

20 जुलाई से मानसून के फिर सक्रिय होने के आसार: मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की शुरुआत हो सकती है।

इसके बाद 22 से 24 जुलाई के दौरान अच्छी वर्षा होने का

अनुमान है। यदि पूर्वानुमान सही रहा तो इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और खेतों में नमी लौटने के साथ खरीफ फसलों की बढ़वार में सुधार होगा।

औसत वर्षा पिछले साल से कम: जिले में 1 जून से 17 जुलाई तक 13.97 इंच औसत वर्षा दर्ज की गई है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 17.51 इंच बारिश हुई थी।

इस तरह इस बार अब तक औसतन 3.54 इंच कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 17 जुलाई को जिले के किसी भी वर्षामापी केंद्र पर बारिश दर्ज नहीं हुई और पूरा दिन मौसम शुष्क बना रहा।

आष्टा में सबसे ज्यादा, श्यामापुर में सबसे कम बारिश: वर्षामापी केंद्रों के अनुसार 17 जुलाई तक जिले में सर्वाधिक वर्षा आष्टा ब्लॉक में 19.29 इंच दर्ज की गई।

इसके अलावा—
जावर - 16.89 इंच
भैरूंदा - 15.31 इंच
इछावर - 14.69 इंच
रेहटी - 13.67 इंच
सीहोर - 12.94 इंच
बुधनी - 11.44 इंच
श्यामापुर - 7.73 इंच (सबसे कम)

कृषि और जलस्तर के लिए अहम होगी अगली बारिश: विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दिनों में होने वाली बारिश खरीफ फसलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी।

इससे खेतों में नमी बढ़ेगी, जलस्तर में सुधार होगा और किसानों को सिंचाई की चिंता से राहत मिल सकेगी। फिलहाल जिले के किसान मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए हुए हैं।

बीसीसीआई अध्यक्ष मन्हास ने सचिव सैकिया को आईसीसी में नई भूमिकाओं के लिए बधाई दी

नई दिल्ली ,एजेसीं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का चेयरमैन चुने जाने और आईसीसी फ्रेंचाइजी लीग कमेटी का सदस्य नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में आयोजित आईसीसी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस के दौरान सैकिया को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। आईसीसी बोर्ड ने अपनी सालाना बैठकों के दौरान दो नई सब-कमेटी बनाने को मंजूरी दी, जिसमें सैकिया को नई गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वह क्रिकेट साउथ अफ्रीका के मोहम्मद मूसाजी और आईसीसी के स्वतंत्र निदेशक रॉस रिवाज के साथ काम करेंगे। सैकिया को नई फ्रेंचाइजी लीग कमेटी का सदस्य भी बनाया गया है, जिसकी अध्यक्षता बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अध्यक्ष तमीम इकबाल करेंगे। इस घोषणा के बाद, मन्हास ने इन नियुक्तियों को क्रिकेट प्रशासन में सैकिया के योगदान की पहचान बताया और खेल के वैश्विक विकास में योगदान देने की उनकी क्षमता पर भरोसा जताया।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, मन्हास ने अपने सहयोगी की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हाल ही में हुई आईसीसी सालाना कॉन्फ्रेंस में आईसीसी गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का चेयरमैन और आईसीसी फ्रेंचाइजी लीग कमेटी का सदस्य चुने जाने पर बीसीसीआई में मेरे सहयोगी देवजीत सैकिया को बहुत-बहुत बधाई। ' मन्हास ने कहा कि ये नियुक्तियां खेल के प्रशासन में सैकिया के लगातार योगदान को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा, 'यह खास नियुक्ति क्रिकेट के प्रशासन और विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और अमूल्य योगदान की सही पहचान है। मुझे भरोसा है कि उनका अनुभव और नजरिया हमारे खेल के वैश्विक विकास को और मजबूत करेगा। ' गवर्नेंस रिव्यू कमेटी उन दो नई बोर्ड सब-कमेटी में से एक है जिन्हें आईसीसी ने क्रिकेट प्रशासन के अहम पहलुओं की देखरेख के लिए बनाया है। गवर्नेंस पैनल में सैकिया के नेतृत्व के साथ-साथ, नई बनी फ्रेंचाइजी लीग कमिटी में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट नामीबिया, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। यह आईसीसी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर को मजबूत करने और तेजी से बढ़ रहे फ्रेंचाइजी क्रिकेट के दायरे पर लगातार ध्यान देने को दर्शाता है।

ल्यूक रोंची छोड़ेंगे न्यूजीलैंड टीम के बैटिंग कोच का पद

बीबीएल में मेलबर्न रेनेगेड्स से जुड़ेंगे

काइस्टचर्च ,एजेसीं। ल्यूक रोंची न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के पद से इस्तीफा देंगे। वह बिग बैश लीग (बीबीएल) में मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम के नए हेड कोच बनेंगे। रोंची अक्टूबर में न्यूजीलैंड के भारत दौरे के दौरान टीम के साथ काम करना जारी रखेंगे और सीरीज खत्म होने के बाद मेलबर्न रेनेगेड्स से जुड़ेंगे। रोंची ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दोनों देशों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। उन्होंने साल 2020 में न्यूजीलैंड टीम के फुल-टाइम बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाली थी। उस समय पीटर फुल्टन के कैंटरबरी का मुख्य कोच बनने के बाद यह पद खाली हुआ था। रोंची ने कहा कि नेशनल टीम के साथ काम करना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा रहा। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों तक खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के साथ काम करने का मौका मिलना उनके लिए गर्व की बात है। उनका हमेशा यही लक्ष्य रहा कि टीम के बल्लेबाज इंटरनेशनल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि इस दौरान टीम के साथ कई यादगार पल बिताने का अवसर मिला, जिन्हें वह हमेशा याद रखेंगे।

रोंची के कार्यकाल में न्यूजीलैंड टीम ने कई बड़ी सफलताएं हासिल कीं। टीम ने 2021 में पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता। इसके अलावा 2021 और 2026 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। न्यूजीलैंड ने 2024 में भारत को उसी के घर में 3-0 से टेस्ट सीरीज में हराया। टीम ने 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन किया। इसी साल जनवरी में भारत के खिलाफ उन्हीं की सरजमीं पर 2-1 से वनडे सीरीज जीती और जून में इंग्लैंड को उनकी ही धरती पर टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया।

न्यूजीलैंड के टेस्ट कप्तान टॉम लाथम ने रोंची की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि रोंची टीम के सबसे अहम सदस्यों में से एक रहे हैं। पहले खिलाड़ी के रूप में और बाद में कोच के तौर पर उन्होंने टीम के माहौल और संस्कृति को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। लाथम ने कहा कि रोंची की कोचिंग में कई खिलाड़ियों के खेल में सुधार आया। वह हमेशा टीम की सफलता के लिए पूरी मेहनत करते रहे और इसका असर मैदान पर साफ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि टीम रोंची को जरूर याद करेगी, लेकिन उनके नए सफर के लिए सभी खिलाड़ी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

इंग्लैंड के फीफा विश्व कप से बाहर होने के बाद बेलिंगहम ने लिखा भावुक पोस्ट

फैंस का किया धन्यवाद

अटलांटा ,एजेसीं। इंग्लैंड के फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद टीम के स्टार खिलाड़ी जूड बेलिंगहम ने भावुक पोस्ट लिखा है। इंग्लैंड को सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। बेलिंगहम ने अपने भावकु पोस्ट में सभी समर्थकों को उनके अविश्वसनीय समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। सेमीफाइनल मैच में एंथनी गॉर्डन द्वारा किए गए गोल की बदौलत इंग्लैंड मुकाबले में 1-0 से आगे चल रहा था। हालांकि, मैच के अंतिम 7 मिनटों में अर्जेंटीना ने दो गोल दागते हुए इंग्लैंड का फाइनल खेलने का सपना एक बार फिर तोड़ दिया। इस निराशाजनक हार के एक दिन बाद, बेलिंगहम ने सोशल मीडिया पर उन सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अमेरिका आकर टीम का समर्थन किया। उन्होंने सभी से भरोसा बनाए रखने की अपील भी की।

बेलिंगहम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर लिखा, 'बीते कुछ हफ्तों और कल के दिन को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। कंसास में हमारे ड्राइवर ने जो बात कही, उसने हमारी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त कर दिया। मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने घर से हमारा हौसला बढ़ाया और अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर अमेरिका आकर हमारा समर्थन किया। हमारे देश के लोगों के बीच जो एकता और प्यार इस अभियान के दौरान देखने को मिला, उसे यहीं खत्म नहीं होने देना चाहिए। अगर हम इसी तरह एकजुट रहें, तो हम आगे भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। ' इंग्लैंड के बाहर होने के बावजूद, बेलिंगहम का टूर्नामेंट शानदार रहा और वह थॉमस ट्यूशेल के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक रहे। इस मिडफील्डर ने टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7 गोल दागे, जिसमें नॉर्वे के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में मैच जिताने वाले दो गोल शामिल रहे। नॉर्वे के खिलाफ बेलिंगहम के दो गोल की बदौलत इंग्लैंड ने चौथी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। राउंड ऑफ 16 में मेक्सिको के खिलाफ भी बेलिंगहम ने दो गोल किए थे।

इंग्लैंड ने नॉकआउट स्टेज में डीआर कांगो, मैक्सिको और नॉर्वे को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इस शानदार प्रदर्शन से टीम के 60 साल से अधिक समय से दूसरे विश्व कप खिताब का इंतजार खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई थी। हालांकि, सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने मैच के अंतिम समय में जोरदार वापसी करते हुए इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

रोहित के वनडे करियर पर छाए संकट के बादल

इंग्लैंड दौरे के बाद टीम में चुने जाने की संभावना कम

कार्डिफ ,एजेसीं। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे वनडे मुकाबले के बाद रोहित शर्मा के एकदिवसीय करियर पर गहरा संकट मंडरा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, लॉर्ड्स वनडे के बाद रोहित के एकदिवसीय टीम में चुने जाने की संभावना काफी कम है। इस मामले की जानकारी रखने वाले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र के अनुसार, अजीत अगरकर की अगुवाई वाली राष्ट्रीय चयन समिति ने 50 ओवर के फॉर्मेट में इस अनुभवी बल्लेबाज को टीम में शामिल न करने का फैसला किया है। वे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले 2027 पुरुष वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को खेलने का ज्यादा मौका देना चाहते हैं। बीसीसीआई के सूत्र ने गुरुवार को 'आईएएनएस' से ??कहा, 'चयनकर्ताओं ने फैसला किया है कि अब वे रोहित शर्मा को वनडे टीम में नहीं चुनेंगे। अगर वह सम्मानजनक तरीके से संन्यास लेना चाहते हैं या तुरंत संन्यास नहीं लेना चाहते हैं, तो यह पूरी तरह से उनका निजी फैसला है। हालांकि, संदेश साफ है कि चयनकर्ता रविवार को लॉर्ड्स में होने वाले मैच के बाद उन्हें वनडे टीम में नहीं चुनेंगे। ' यह फैसला अनुभवी बल्लेबाज की हालिया फॉर्म को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण लिया गया है। सोफिया गार्डन्स में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में उनकी 26 रन की संघर्षपूर्ण पारी से यह साफ पता चलता है। बीसीसीआई सूत्र ने आगे कहा, 'चर्चा यह है कि रोहित कुछ समय से अपनी बेहतरीन लय में नहीं खेल रहे हैं। वहीं, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी, जिन्होंने हाल ही में वनडे में अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें बाहर बैठना पड़ रहा है। इसी बड़े अंतर ने चयनकर्ताओं को अपनी लंबी अवधि की रणनीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर किया है। अभी तो यह लगभग तय लग रहा है कि लॉर्ड्स में रविवार का मैच भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी के तौर पर रोहित का आखिरी मैच हो सकता है। '

हालांकि, अभी यह पता नहीं चल पाया है कि चयन समिति ने रोहित को पहले ही इस फैसले के बारे में बता दिया है कि इंग्लैंड का दौरा रविवार को खत्म होने के बाद उन्हें वनडे टीम से हटा दिया जाएगा। रोहित पहले ही टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने भारत को 2024 पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने के कुछ समय बाद ही यह फैसला लिया था। वह 50-ओवर वाला फॉर्मेट इसलिए खेल रहे हैं, क्योंकि वह 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। 7 मई, 2025 को इंग्लैंड के पांच मैचों के दौरे से पहले रोहित ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया और जल्द ही शुभमन गिल को

वनडे कप्तान बना दिया गया था। 287 वनडे मैचों में रोहित ने 11,757 रन बनाए हैं और 50-ओवर के फॉर्मेट में सबसे आक्रामक और भरोसेमंद ओपनर्स में से एक के तौर पर भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है। रोहित ने 56 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की। उनकी आक्रामक सोच और अच्छी कप्तानी की बदौलत भारत 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा। इसके बाद उनकी कप्तानी में भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, जो यूएई में खेली गई थी।

क्वार्टर फाइनल मैच से ओकुहारा के हटने के बाद सेमीफाइनल में पहुंचीं पीवी सिंधु

टोक्यो ,एजेसीं। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने शुक्रवार को जापान ओपन सुपर 750 के सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला नोजोमी ओकुहारा से होना था, लेकिन वह चोट के कारण मैच में हिस्सा नहीं ले सकीं। यह इस सीजन में सिंधु का तीसरा सेमीफाइनल है। इससे पहले वह मलेशिया सुपर 1000 और ऑस्ट्रेलिया सुपर 500 के सेमीफाइनल में पहुंची थीं। इसके साथ ही, 2023 डेनमार्क ओपन के बाद यह उनका पहला सुपर 750 सेमीफाइनल है। 31 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की निगाहें इस सीजन का पहला खिताब जीतने पर होंगी। सेमीफाइनल मुकाबले में उनका सामना टोक्यो ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की विश्व की नंबर 4 चीनी खिलाड़ी चेन युफेई से होगा। सिंधु और चेन युफेई के बीच अब तक कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। हालांकि, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में सिंधु उनसे 6-8 से पीछे हैं। सिंधु को युफेई के खिलाफ पिछले पांच मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। सेमीफाइनल में जीत न केवल सिंधु के हारने के इस सिलसिले को खत्म करेगी, बल्कि लगभग तीन साल में उनके पहले सुपर 750 फाइनल में पहुंचने का रास्ता भी साफ होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ सुपर 750 टूर्नामेंट में अब भारत की एकमात्र दावेदार हैं। सिंधु ने प्री-क्वार्टर फाइनल मैच में विश्व की नंबर 5 खिलाड़ी हान युए को सिर्फ 35 मिनट में हराया था।

'आरआर छोड़ना आसान नहीं था',

● सीएसके में जाने की पूरी कहानी संजू सैमसन ने खुद बताई

नई दिल्ली,एजेसीं। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के लिए आईपीएल 2026 एक अलग अनुभव रहा। सैमसन इस बार आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) की गुलाबी नहीं, बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की पीली जर्सी में दिखे। आरआर में लंबा समय बिताने के बाद सीएसके में पहुंचे सैमसन ने अपनी पुरानी आईपीएल टीम और उसे छोड़ने के समय को याद किया है। सैमसन ने जियोस्टार के शो 'सुपरस्टार्स' पर कहा, 'आरआर से अलग होना मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला था। मेरा मानना ??है कि जब आप कुछ समय तक किसी टीम के लिए खेलते हैं, तो आपको लगने लगता है कि यह आपकी टीम है और कोई आपको हटा नहीं सकता। हालांकि, मुझे हमेशा यह एहसास रहता था कि किसी भी जगह पर हर किसी का समय सीमित होता है। आप अपना काम करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आईपीएल 2025 के बाद एक ऐसा समय आया जब मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मैंने खुद से कहा कि लड़के तैयार हैं और आरआर संजू सैमसन के बिना खेलने के लिए तैयार है। मैंने उसी समय आरआर छोड़ने के बारे में सोचा।' सीएसके में जाने के अपने फैसले पर सैमसन ने सबसे पहले पूर्व कप्तान एमएस धोनी और मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के प्रभाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'जब आप कहीं और जाने के बारे में सोचते हैं, तो आप सोचते हैं कि कहां जाएं और किस टीम में शामिल हों।

उन्होंने कहा,

'दूसरे खिलाड़ियों से सीएसके के बारे में जो सुना था, उसके आधार पर मुझे लगा कि यह फ्रेंचाइजी मेरे लिए सही है। अगर मैं वहां जाता हूं, तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने ऐसी इच्छा की थी, लेकिन ट्रेड एक मुश्किल चीज है।

बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीजः

हंसिका को सिल्वर से करना पड़ा संतोष, रजत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल

बुडापेस्ट ,एजेसीं। भारत की हंसिका लांबा ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में महिलाओं के 55 किलोग्राम फ्रीस्टाइल इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। हालांकि, वह गोल्ड मेडल जीतने से चूक गई और उन्हें फाइनल में यूक्रेन की नतालिया क्लीवचुत्स्का के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। 19 वर्षीय हंसिका को क्लीवचुत्स्का के खिलाफ 0-5 से हार झेलनी पड़ी। हंसिका लांबा ने क्वार्टर फाइनल में तुर्की की तुबा डेमिर को 8-4 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल में जर्मनी की अनास्तासिया ब्लेवास के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 10-7 से जीत दर्ज की थी। 2-7 से पिछड़ने के बाद, लांबा ने चार बार टेकडाउन करके जीत हासिल की और फाइनल का टिकट हासिल किया। वह इस साल शानदार फॉर्म में रही हैं और अपने दो अन्य अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट–एशियन चैंपियनशिप और उलानबटार ओपन में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं।महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में प्रियांशी प्रजापत को रेपचेज के जरिए मौका मिलने के बाद ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में इक्वाडोर की जैकलीन मोलोकाना से 4-2 से हार का सामना करना पड़ा। प्रियांशी ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की थी। उन्होंने पैन-अमेरिकन चैंपियन अमेरिका की केटी गोमेज को 'फॉल' के जरिए हराया था। मुकाबले में गोमेज ने शुरुआत में बढ़त बना ली थी, लेकिन प्रियांशी ने बेहतरीन वापसी करते हुए उनके पैरों पर हमला किया और उन्हें पिन करके मुकाबला अपने नाम कर लिया।

हालांकि, क्वार्टर फाइनल में प्रियांशी को चीन की फेंग जिकि के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। फेंग जिकि ने यह मुकाबला तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीता। चीन की फेंग जिकि पेरिस ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडल विजेता भी रह चुकी हैं।

एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान

नई दिल्ली,एजेसीं। हॉकी इंडिया ने एफआईएच महिला विश्व कप 2026 के लिए भारत की 20 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान सलीमा टेटे के हाथों में सौंपी गई है। भारतीय महिला हॉकी टीम के हेड कोच स्योर्ड मारिजने ने चुनी गई टीम को बेहद संतुलित बताया है। विश्व कप का आयोजन 15 से 30 अगस्त के बीच होना है। टूर्नामेंट की मेजबानी नीदरलैंड और बेल्जियम मिलकर करेंगे। बेंगलुरु में नेशनल कैंप में ट्रेनिंग कर रही इस टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और होनहार युवा खिलाड़ियों का मिश्रण है। इन युवा खिलाड़ियों ने हाल के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में सभी को प्रभावित किया है, खासकर पिछले महीने न्यूजीलैंड में हुए एफआईएच नेशंस कप में टीम का प्रदर्शन दमदार रहा था और भारत ने बिना कोई मैच हारे खिताब पर कब्जा जमाया था। टीम में सविता और बिचू देवी खारीबम को गोलकीपर के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि डिफेंस यूनिट में इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरामबम, लालथंतलुंगी, ज्योति और शिल्पी डबास शामिल हैं। मिडफील्ड में कप्तान सलीमा के साथ निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो, नेहा और दीपिका सोरेंग को रखा गया है। वहीं, फॉरवर्ड लाइन में लालरेम्सियामी, रुतुजा दादासो पिसल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर और ब्यूटी डुंगडुंग को जगह दी गई है।

विश्व कप के लिए चुनी गई टीम को लेकर बातचीत करते हुए कोच मारिजाने ने कहा, 'हमने खिलाड़ियों का एक संतुलित ग्रुप चुना है जो इस गर्मी में आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार है। टीम ने टूर्नामेंट से पहले कड़ी मेहनत की है और हमें इस ग्रुप की काबिलियत पर भरोसा है। हम दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेलने और सबसे बड़े मंच पर शानदार प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित हैं। '

● एफआईएच हॉकी महिला विश्व कप 2026 के लिए भारत की 20 सदस्यीय टीमः

गोलकीपरः सविता, बिचू देवी खारीबम
डिफेंडरः इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरामबम, लालथंतलुंगी, ज्योति, शिल्पी डबास
मिडफील्डरः निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो, सलीमा टेटे (कप्तान), नेहा, दीपिका सोरेंग
फॉरवर्डः लालरेम्सियामी, रुतुजा दादासो पिसल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर, ब्यूटी डुंगडुंग।

ग्रामीण स्वच्छता का मॉडल बन रहा बालोद, ग्रे-वॉटर प्रबंधन से गांव हो रहे स्वच्छ और जल-सुरक्षित

अपशिष्ट जल के वैज्ञानिक प्रबंधन से भू-जल संवर्धन को मिला बढ़ावा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। स्वच्छ एवं जल-सुरक्षित गांवों का निर्माण जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जैसी पहलों के माध्यम से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाना, जल का संरक्षण करना और ठोस/तरल कचरे का उचित प्रबंधन कर बीमारियों से बचाव करना है। ग्रे-वॉटर (रसोई और स्नानघर का गंदा पानी) का उचित प्रबंधन गांवों को स्वच्छ और जल-सुरक्षित बना रहा है। सोख्ता गड्ढों, किचन गार्डन और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली के माध्यम से, इस पानी को उपचारित करके पुनः उपयोग में लाया जा रहा है। यह जलभराव और बीमारियों को रोकता है।

ग्रे-वॉटर प्रबंधन से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को नया आयाम मिला मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में स्वच्छ एवं जल-सुरक्षित गांवों के निर्माण की दिशा में बालोद जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रे-वॉटर (रसोई, स्नानघर एवं कपड़े धोने के बाद निकलने वाले पानी) के वैज्ञानिक प्रबंधन की दिशा में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। बालोद में सोकपिट, मैजिक पिट एवं अन्य ग्रे-वॉटर प्रबंधन संरचनाओं के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को नया आयाम मिला है। इससे न केवल गांवों में जलभराव और गंदगी की समस्या का समाधान हुआ है, बल्कि भू-जल संवर्धन और

पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिल रही है। घरेलू अपशिष्ट जल का हो रहा वैज्ञानिक प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकलने वाला ग्रे-वॉटर पहले सड़कों एवं गलियों में बहता था, जिससे जलभराव, दुर्गंध, गंदगी तथा मच्छरों के पनपने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती थीं। अब सोकपिट एवं मैजिक पिट जैसी संरचनाओं के माध्यम से इस पानी का सुरक्षित निस्तारण किया जा रहा है। पानी सीधे भूमि में समाहित होने से गांवों की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार आया है और ग्रामीणों को साफ-सुथरा एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो रहा है। भू-जल पुनर्भरण और जल संरक्षण को मिल रही नई दिशा ग्रे-वॉटर प्रबंधन की इन संरचनाओं से वर्षा जल एवं घरेलू अपशिष्ट जल का भूमि में पुनर्भरण हो रहा है, जिससे भू-जल स्तर को बनाए रखने में सहायता मिल रही है। यह पहल जल संरक्षण के साथ भविष्य की जल आवश्यकताओं को सुरक्षित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम में भी मिल रही सफलता खुले में गंदा पानी जमा नहीं होने से जल प्रदूषण में कमी आई है और मच्छरों के प्रजनन पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। इसके परिणामस्वरूप संक्रामक बीमारियों के प्रसार का खतरा भी कम हुआ है। कई ग्रामों में उपचारित जल का उपयोग पौधारोपण एवं हरित क्षेत्रों के संरक्षण में किया जा रहा है, जिससे जल के पुनः उपयोग को भी बढ़ावा मिल रहा है। जनभागीदारी से साकार होगा स्वच्छ और जल-सुरक्षित गांवों का सपना जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि सोकपिट, मैजिक पिट एवं अन्य ग्रे-वॉटर प्रबंधन संरचनाओं का नियमित उपयोग एवं रखरखाव करें तथा इनमें किसी भी प्रकार का ठोस कचरा न डालें। जनसहभागिता से ही यह अभियान और अधिक प्रभावी बनेगा तथा स्वच्छ, स्वस्थ, पर्यावरण-अनुकूल एवं जल-सुरक्षित गांवों के निर्माण का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकेगा।

सीसी रोड, नाली और चबूतरा निर्माण के लिए 13.26 लाख मंजूर

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने दुर्ग जिले के अमलेश्वर नगर पालिका में सीसी रोड, आरसीसी नाली और चबूतरा निर्माण के लिए 13 लाख 26 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास ने अमलेश्वर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-12 में सीसी रोड के लिए 9 लाख 73 हजार रुपए और शिव मंदिर के बाजू में चबूतरा निर्माण के लिए 2 लाख 28 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। विभाग ने वार्ड क्रमांक-12 में ही आरसीसी नाली के निर्माण के लिए एक लाख 25 हजार रुपए मंजूर किए हैं।

मनरेगा का चेक डेम बना किसानों की नई उम्मीद, 12.5 एकड़ खेतों तक पहुंचेगा सिंचाई का पानी

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। कभी बारिश का पानी बह जाने से गर्मी में जल संकट झेलने वाले मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के भरतपुर विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत माड़ीसरई के किसानों के लिए अब हालात बदलने की उम्मीद जगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अंधेरगढ़ नाला पर निर्मित पक्का चेक डेम गांव में जल संरक्षण और सिंचाई का स्थायी आधार बनकर उभरा है। इससे लगभग 12.5 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की संभावना है। ग्रामीणों के अनुसार पहले बरसात का अधिकांश पानी नाले के जरिए बह जाता था। इसके कारण गर्मी के दिनों में खेतों और पेयजल दोनों के लिए संकट पैदा हो जाता था। अब चेक डेम बनने से वर्षा जल का संचयन होगा और किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। इस परियोजना के निर्माण में 1,185 मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ। इससे गांव के श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर काम मिला और रोजगार के लिए बाहर पलायन की जरूरत भी कम हुई। निर्माण कार्य में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। चेक डेम से केवल सिंचाई ही नहीं, बल्कि भूजल स्तर में सुधार की भी उम्मीद है। वर्षा जल के संरक्षण से आसपास के कुओं और हैंड पंपों में पानी की उपलब्धता बढ़ने के साथ मिट्टी के कटाव पर भी नियंत्रण मिलेगा। इससे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।आधारित खेती तक सीमित नहीं रहेंगे। सिंचाई सुविधा मिलने से धान के अलावा दलहन, तिलहन और अन्य फसलों की खेती का दायरा भी बढ़ सकेगा, जिससे कृषि उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि होने की संभावना है।

870 ग्राम की नन्ही सी जान को मिला नया जीवन जिला अस्पताल कवर्धा की एसएनसीयू टीम की मेहनत लाई रंग

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। जिला अस्पताल कवर्धा ने नवजात शिशु चिकित्सा के क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए मानवता और चिकित्सा सेवा का प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। अस्पताल की स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में मात्र 870 ग्राम वजन के अति समयपूर्व (एक्सट्रीम प्रीटर्म) जन्मे नवजात शिशु का सफल उपचार कर उसे स्वस्थ अवस्था में घर भेजा गया। जन्म के समय शिशु की स्थिति अत्यंत गंभीर थी और उसके जीवित रहने की संभावना बेहद कम मानी जा रही थी, लेकिन चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के समर्पित प्रयासों ने इस नन्ही जान को नया जीवन प्रदान किया। जन्म के तुरंत बाद नवजात को जिला अस्पताल की एसएनसीयू में भर्ती किया गया, जहां शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. शलिल मिश्रा के मार्गदर्शन में डॉ. त्रिभुवन जायसवाल, चिकित्सा अधिकारी (एसएनसीयू) सहित विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ ने चैबीसों घंटे उसकी गहन निगरानी की। उपचार के दौरान नवजात को श्वसन सहायता, शरीर का तापमान नियंत्रित रखने, संक्रमण से सुरक्षा, संतुलित पोषण तथा अन्य आवश्यक नवजात गहन चिकित्सा सेवाएं लगातार उपलब्ध कराई गईं। लगभग एक माह तक चले सतत उपचार, विशेषज्ञ निगरानी और समर्पित देखभाल के परिणामस्वरूप नवजात के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हुआ। इस अवधि में उसका वजन 870 ग्राम से बढ़कर 1600 ग्राम हो गया। चिकित्सकीय परीक्षणों में पूरी तरह स्थिर पाए जाने के बाद उसे स्वस्थ अवस्था में डिस्चार्ज कर परिजनों को सौंप दिया गया।

महतारी वंदन योजना बनी आत्मनिर्भरता की नई पहचान

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना मुंगेली जिले की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। जिले की अनेक महिलाएं इस राशि का उपयोग स्वरोजगार एवं परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में कर रही हैं। इसी कड़ी में ग्राम सारधा की श्रीमती पुष्पा साहू महतारी वंदन योजना से प्रतिमाह प्राप्त होने वाली एक हजार रुपये की राशि का उपयोग अपने सिलाई कार्य में कर रही हैं। योजना से मिलने वाली नियमित सहायता से उन्होंने सिलाई के लिए आवश्यक सामग्री एवं अन्य जरूरतों की पूर्ति कर अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। इससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है पुष्पा साहू ने बताया कि पहले सीमित संसाधनों के कारण सिलाई कार्य को नियमित रूप से आगे बढ़ाना कठिन था, लेकिन अब योजना से मिलने वाली राशि उनके लिए बड़ा सहारा बन गई है। इससे वे अपने हुनर का बेहतर उपयोग कर रही हैं और घर बैठे रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और सम्मान को बढ़ाने वाली योजना है। इससे महिलाओं को अपनी क्षमता के अनुसार स्वरोजगार अपनाने और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में भागीदारी निभाने का अवसर मिल रहा है।

किसानों के लिए सुरक्षा कवच बनेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु आवेदन 31 जुलाई तक

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुंगेली जिले में इस वर्ष वर्षा की अनिश्चितता को देखते हुए किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक प्रभावी सुरक्षा कवच साबित हो सकती है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे 31 जुलाई 2026 तक अपनी अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराकर संभावित प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से स्वयं को सुरक्षित करें। उप संचालक कृषि श्रीमती वीणा ठाकुर ने बताया कि जिले में इस वर्ष अब तक सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है, जिससे खरीफ फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी और विपरीत परिस्थितियों में राहत का माध्यम बनेगी। योजना के तहत धान (सिंचित एवं असिंचित), सोयाबीन, अरहर (तुअर), मक्का, उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी तथा रागी सहित अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराया जा सकता है। किसानों को केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रति हेक्टेयर किसान अंश राशि धान (सिंचित) के लिए 1,320 रुपये, धान (असिंचित) 946 रुपये, सोयाबीन 902 रुपये, अरहर 770 रुपये, मक्का 792 रुपये, उड़द एवं मूंग 484 रुपये, मूंगफली 924 रुपये, कोदो 352 रुपये, कुटकी 374 रुपये तथा रागी 330 रुपये निर्धारित की गई है। योजना के अंतर्गत बुवाई नहीं होने, फसल कटाई प्रयोग के आधार पर उपज में कमी, ओलावृष्टि, बादल फटना, प्राकृतिक आकाशीय बिजली तथा कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर बेमौसम बारिश एवं चक्रवात से हुई क्षति जैसी परिस्थितियों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। किसानों को समझाइश दी गई है कि वे निकटतम बैंक शाखा, सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र (सीएससी) अथवा प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से समय-सीमा के भीतर बीमा अवश्य कराएं।

विलंबित मानसून के बीच धान किसानों के लिए आईसीएआर-एनआईबीएसएम की विशेष सलाह

पर्याप्त बारिश मिलते ही करें रोपाई, देरी की स्थिति में कम अवधि वाली किस्मों और वैकल्पिक फसलों पर दें ध्यान

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। दक्षिण-पश्चिम मानसून में देरी और छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में वर्षा की अनिश्चितता को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान (आईसीएआ-एनआईबीएसएम), रायपुर ने प्रदेश के धान किसानों के लिए विशेष कृषि परामर्श जारी किया है। संस्थान ने किसानों से खरीफ मौसम में फसल की सफल स्थापना और संभावित उपज हानि को कम करने के लिए मौसम की स्थिति के अनुरूप समय पर वैज्ञानिक एवं आकस्मिक कृषि उपाय अपनाने की अपील की है। संस्थान के अनुसार, पर्याप्त वर्षा होते ही किसान स्वस्थ 20-25 दिन पुराने पौधों से अनुशंसित दूरी पर धान की रोपाई शीघ्र पूरी करें। रोपाई में अधिक देरी होने की स्थिति में कम से मध्यम अवधि में पकने वाली धान की किस्मों को प्राथमिकता दी जाए। जहां रोपाई

संभव न हो, वहां अंकुरित बीजों से ड्रम सीडर अथवा छिड़काव विधि द्वारा धान की सीधी बुवाई भी अपनाई जा सकती है। संस्थान के निदेशक डॉ. पी.के. राय ने कहा कि बदलती जलवायु और अनिश्चित वर्षा की परिस्थितियों में समय पर वैज्ञानिक फसल प्रबंधन तथा आकस्मिक योजना अपनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने किसानों से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कृषि सलाह के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विशेषज्ञों के नियमित संपर्क में रहने का आग्रह किया।संस्थान ने संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन पर जोर देते हुए फास्फोरस और पोटाश की अनुशंसित मात्रा आधार खाद के रूप में देने तथा नत्रजन उर्वरक का प्रयोग फसल की आवश्यकता के अनुसार विभाजित मात्रा में करने की सलाह दी है। भारी वर्षा की संभावना से ठीक पहले यूरिया का प्रयोग नहीं करने को कहा गया है, ताकि पोषक तत्वों की हानि को कम किया जा सके को समय पर खरपतवार नियंत्रण, खेत में उचित नमी बनाए रखने और जलभराव की स्थिति में प्रभावी जल निकासी सुनिश्चित करने की सलाह भी दी गई है। साथ ही तना छेदक, पत्ती लपेटक जैसे प्रमुख कीटों तथा ब्लास्ट और जीवाणुजनित पत्ती झुलसा जैसे रोगों की नियमित निगरानी करने और आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक अनुशंसाओं पर आधारित पौध संरक्षण उपाय अपनाने को कहा गया है। संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ. पंकज शर्मा ने कहा कि विलंबित मानसून की स्थिति में फसल की प्रारंभिक अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किसानों को खेत संबंधी कार्यों में अनावश्यक देरी से बचते हुए संतुलित पोषण, प्रभावी खरपतवार नियंत्रण और कीट-रोगों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में लंबे समय तक वर्षा की कमी के कारण धान की खेती प्रभावित होने की आशंका है, वहां स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, तिल और मोटे अनाज जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती पर विचार किया जा सकता है।

सिम्स बिलासपुर में डॉक्टरों का कमाल

वर्षीय मासूम की आहार नली से सफलतापूर्वक निकाला गया सिक्का, बची जान

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर के कान, नाक एवं गला (ईएनटी) विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने तत्परता दिखाते हुए एक 6 वर्षीय मासूम की जान बचा ली है। बैगा जनजाति के इस बालक ने खेलते समय गलती से सिक्का निगल लिया था, जो उसकी आहार नली (अन्ननली) में फंस गया था। डॉक्टरों की टीम ने बेहद जटिल और आपातकालीन स्थिति में सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर सिक्के को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार, बिलासपुर जिले के कोटा तहसील अंतर्गत ग्राम सरगोंड का निवासी 6 वर्षीय

बालक नरेंद्र खेलते समय सुबह करीब 7 बजे अचानक सिक्का निगल गया। इसके तुरंत बाद उसे कुछ भी निगलने में अत्यधिक परेशानी होने लगी। परिजन आनन-फानन में उसे पेंड्रा के एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया। बालक को शाम करीब 6.30 बजे सिम्स लाया गया, जिसके बाद अस्पताल का पूरा अमला सक्रिय हो गया। रेडियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह ने तत्काल एक्स-रे कर अन्ननली के ऊपरी भाग (श्वासनली के मुहाने के ठीक पीछे) में फंसे सिक्के की सटीक लोकेशन की पहचान की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉ. मधुमिता मूर्ति की टीम ने बच्चे को सामान्य एनेस्थीसिया दिया। इसके बाद ईएनटी विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. आरती पाण्डेय एवं सहायक प्राध्यापक डॉ. श्वेता मित्तल के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने रिजिड इसोफैगोस्कोपी तकनीक के जरिए अत्यंत सावधानी से सिक्के को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

थयात्रा महोत्सव में शामिल हुए राज्यपाल डेका

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। राज्यपाल श्री रमेन डेका रथ यात्रा पर्व के अवसर पर आज गायत्री नगर रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित महाप्रभु श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। राज्यपाल श्री डेका एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर 'छेरा-पहरा' की रस्म निभाई। राज्य की प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी ने श्री जगन्नाथ जी की विधि-विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

सीएम हेल्पलाइन 1076 से श्रीमती हिमाद्री निराला को मिला उज्ज्वला गैस कनेक्शन

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 इसी दिशा में एक भरोसेमंद माध्यम बनकर उभरी है, जहां प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से श्रीमती हिमाद्री निराला की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित समस्या का महज दो दिनों में समाधान कर उन्हें गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। श्रीमती हिमाद्री निराला ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन प्राप्त करने

के लिए बिर्रा इंडेन ग्रामीण वितरक के यहां आवेदन किया था। आवेदन स्वीकृत होने के बावजूद उन्हें गैस कनेक्शन नहीं मिल पाया। समस्या के समाधान के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होते ही खाद्य विभाग द्वारा मामले की जांच की गई। जांच में पाया गया कि श्रीमती निराला वर्तमान में ग्राम दुरुग, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में निवास कर रही हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक-2026

जोखिम आधारित बिजनेस परमिशन व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा छत्तीसगढ़

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने उद्योग और कारोबार को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आज 'छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026' पारित कर दिया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए जोखिम आधारित (रिस्क बेस्ड) एवं विश्वास आधारित (ट्रस्ट बेस्ड) बिजनेस परमिशन सिस्टम लागू होगा। इस विधेयक का उद्देश्य उद्योगों एवं कारोबार की स्थापना और संचालन संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनावश्यक अनुपालनों को कम करना तथा विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अधिक पारदर्शी, तेज और उद्यम-अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तैयार करना है। विधेयक के तहत उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण उनके आकार और गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर विभिन्न जोखिम श्रेणियों में किया जाएगा। कम जोखिम वाले छोटे कारोबारों को सरल एवं त्वरित मंजूरी मिलेगी, जबकि अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं के लिए आवश्यक तकनीकी परीक्षण और समयबद्ध स्वीकृति की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी। इससे छोटे कारोबारियों को बड़े उद्योगों जैसी जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा।

नई व्यवस्था के अंतर्गत कम जोखिम वाले उद्यमों में बार-बार होने वाले विभागीय निरीक्षणों के स्थान पर सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा लाइसेंसधारी अभियंता, आर्किटेक्ट या अन्य अधिकृत पेशेवरों द्वारा प्रमाणन की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे अनुमतियों की प्रक्रिया तेज, सरल और अधिक जवाबदेह बनेगी। विधेयक के तहत हर वर्ष लाइसेंस या अनुमति के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली लागू की जाएगी। इससे उद्यमियों को अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत मिलेगी और वे अपने कारोबार के विस्तार एवं संचालन पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। एमएसएमई इकाइयों के लिए जल प्रदाय संबंधी अनुमति स्व-घोषणा के आधार पर, सोसायटी अथवा फर्म का पंजीयन समयबद्ध प्रक्रिया से तथा भवन अनुज्ञा सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा अधिकृत विशेषज्ञ के प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदान की जा सकेगी। निर्धारित समय-सीमा में संबंधित विभाग द्वारा निर्णय नहीं लेने की स्थिति में पात्र मामलों में अनुमति स्वतः स्वीकृत (ऑटो अप्रूवल) मानी जाएगी। हालांकि अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं में तकनीकी परीक्षण एवं भौतिक निरीक्षण की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक / प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा विप्र एक्सप्रे प्रेस सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय वार्ड 14 हल्दीबाड़ी एमसीबी छत्तीसगढ़ से प्रकाशित,संपादक संदीप द्विवेदी आर .एन .आई नं . सी टी एच आई एन /25/ए 1478 फोन नं .7974467831,9589645803, mediaauditor1@gmail .com पीआइबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार , सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा